आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650

इंदौर, शुक्रवार 30 जनवरी 2026

■ वर्ष : 5 ■ अंक : 81
■ पृष्ठ : 6 ■ मूल्य : 2

dainikindoresanket.com
dainikindoresanket
dainikindoresanket
dainikindoresanket24@gmail.com

सांध्य दैनिक

इंदौर संकेत

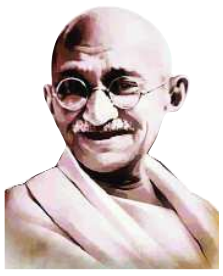

राष्ट्रपिता को नमन...

अंदर के पन्नों पर...

प्रमुख सड़कें और फुटपाथ होंगे अतिक्रमण से मुक्त

पेज-2

दीपिका की जगह लेंगी साई पल्लवी

पेज-5

बीआरटीएस पर एलिवेटेड कॉरिडोर की तैयारी

पेज-6

बर्फीली हवाओं से जूझ रहे इंदौर शहर में कल से बारिश का अलर्ट

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● शहर में बारिश का दौर फिर लौटेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 31 जनवरी और 1-2 फरवरी को इंदौर सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) की वजह से ऐसा होगा। इससे पहले शुक्रवार को प्रदेश के करीब आधे हिस्से में घना कोहरा छा रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह भोपाल, ग्वालियर, चंबल, सागर, जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग के 24 जिलों में कहीं हलका तो कहीं मध्यम कोहरा छा रहा है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। 31 जनवरी, 1-2 फरवरी को बारिश होने का अलर्ट है। गौरतलब है कि गत 3-4 दिन से इंदौर शहर में बर्फीली हवाएं चलने से मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह 9 बजे तक आद्रता का प्रभाव बना रहता है, जिसके चलते एक किलोमीटर से अधिक की दृश्यता नहीं दिख रही है। पहाड़ी राज्य- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।

यूजीसी विवाद : बीजेपी ने अपने 'बयानवीरों' पर लगाया लगाम

नई दिल्ली (एजेंसी) ● यूजीसी विवाद में भारी फजीहत के बाद बीजेपी अब बैकफुट पर नजर आ रही है। देश भर में इस फैसले के विरोध और सुप्रीम कोर्ट से इसपर रोक लगने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के बयानवीरों से मामले में परेशान है। बीजेपी ने अपने सभी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को कहा है कि वे यूजीसी और उससे जुड़े विषयों पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या बयान देने से परहेज करें। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वे इस निर्देश का कड़ाई से पालन करें। दरअसल, पार्टी ने राजनीतिक तौर पर संवेदनशील यूजीसी विवाद के बढ़ने पर अपने नेताओं को इस मुद्दे पर बयान देने से मना किया था पर कुछ सांसदों और मंत्रियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस पर बयान दिया।

इसके बाद बीजेपी संसदीय दल की तरफ से सभी सांसदों और मंत्रियों को बयान देने से परहेज करने का निर्देश दिया गया है। गुरुवार को बीजेपी प्रवक्ताओं की बैठक में भी यूजीसी मामले पर बयान या डिबेट में जाने से मना किया गया। बता दें कि यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए यूजीसी नियम की भाषा अस्पष्ट है। इसका गलत इस्तेमाल संभव है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दखल नहीं देंगे को खतरनाक परिणाम होंगे। सीजेआई ने कहा कि स्थिति का फायदा उठाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल यूजीसी का 2012 वाला नियम लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूजीसी को नोटिस जारी किया।

सामान्य वर्ग में जबरदस्त आक्रोश था

यूजीसी के नए नियमों को लेकर सामान्य वर्ग के लोगों में जबरदस्त आक्रोश था। सरकार की सफाई के बावजूद गुस्से की आग बुझी नहीं थी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया, जिसे एक वर्ग अपने लिए जीत मान रहा है तो दूसरा पक्ष इसे सरकार के लिए झटका बता रहा है। मगर सवाल जीत-हार का नहीं है बल्कि इस नियम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, वो बहुत गंभीर है।

महाराष्ट्र में आने वाला था बड़ा ट्विस्ट

8 फरवरी को एक हो रहे थे एनसीपी के दोनों गुट

मुंबई (एजेंसी) ● महाराष्ट्र की राजनीति में जल्द बड़ी उठा पटक के आसार हैं। खबर है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट फरवरी में फिर से एक होने की घोषणा करने वाले थे, लेकिन अजित पवार के निधन के कारण इसे टाल दिया गया है। एक गुट की अगुवाई अजित के पास थी। जबकि, दूसरे गुट एनसीपी एसपी के प्रमुख वरिष्ठ नेता शरद पवार थे। हाल ही में चाचा और भतीजे पुणे स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक हुए थे, जिसके बाद एनसीपी के एक होने की अटकलें तेज हो गईं थीं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, एनसीपी के दोनों गुट 8 फरवरी को साथ आने का ऐलान करने वाले थे। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि विलय को लेकर चर्चाएं काफी आगे बढ़ गई थीं और नेता जिला परिषद चुनाव के बाद औपचारिक ऐलान करने वाले थे।

न्यूज ब्रीफ

- असम : अमित शाह आज 1715 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन
- चांदी में बड़ी गिरावट : 24000 रुपये हुई सस्ती, सोना भी 8000 रु. हुआ
- पी.टी. उषा के पति वी. श्रीनिवासन का निधन, 67 वर्ष की उम्र में हुआ देहांत
- सबरीमाला गोल्ड चोरी मामले में एसआईटी ने एक्टर जयराम का बयान रिकॉर्ड किया
- इंस्टाग्राम पर लौटे विराट कोहली, एक्टिव हुआ अकाउंट
- अन्ना हजारे आज से रालेगणसिद्धी में आमरण अनशन करेंगे
- बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे के लिए जाएंगे गोवा
- हम ईरान से बात करने की योजना बना रहे हैं : ट्रंप

आरएसएस का नवाचार : बहुभाषियों को एकजुट करने की अनूठी कवायद

संघ पदाधिकारी सुरेश सोनी, दीपक विस्पुते रहेंगे मौजूद

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● प्रदेश में बस्ती स्तर पर हिंदू एकता सम्मेलनों के बाद अब अलग-अलग भाषायी लोगों को एकजुट करने की कवायद शुरू की गई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ समर्थित मातृभाषा मंच के बैनर तले यह प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। भोपाल में होने वाले इस कार्यक्रम में संघ के सह सरकार्यवाह रहे सुरेश सोनी और वरिष्ठ पदाधिकारी दीपक विस्पुते भी मौजूद रहेंगे।

भोपाल के बहुभाषी समाज को सहभागी बनाने सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी और उनके पारंपरिक व्यंजनों का आस्वाद इसका आकर्षण रहेगा। भेल दशहरा मैदान पर 30 जनवरी से 1 फरवरी तक होने वाले महोत्सव

का सांस्कृतिक एकजुटता के साथ सियासी महत्व भी है। हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव और 2023 के मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में भाषायी एकजुटता के अच्छे नतीजे सामने आ चुके हैं। भोपाल में मातृभाषा मंच ने हिंदी के अलावा भोजपुरी, मैथिली, मराठी, छत्तीसगढ़ी, उड़िया, बंगाली, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, तमिल, तेलगु, उत्तराखंडी, असमिया, संस्कृत, कन्नड़, नेपाली, पंजाबी और मलयाली सहित करीब डेढ़ दर्जन भाषायी लोगों को एकजुट करने का बीड़ा उठाया है। भारतीय भाषाओं की संस्कृतियों के समारोह सहित समापन सत्र के दौरान संघ शताब्दी वर्ष पर केंद्रित राष्ट्र सर्वोपरि कार्यक्रम की प्रस्तुति भी रखी गई है।

ये हैं प्रमुख आकर्षण-वंदे मातरम की नाट्य प्रस्तुति और गुरु तेग बहादुरजी पर केंद्रित नाटिका का मंचन। भगवान झूलेलाल एवं भगवान बिरसा मुंडा पर केंद्रित नाटिका का मंचन एवं विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां।

मोहन सरकार का इंदौर और भोपाल ईडी को फ्री हैंड, आरोपी नहीं छिपा सकेंगे संपत्तियां

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● मध्यप्रदेश में इन दिनों ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) खासी सक्रिय है। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर लगातार केस दर्ज हो रहे हैं। साथ ही संपत्तियां अटैच की जा रही हैं। हाल ही में कई चालान भी ईडी ने स्पेशल कोर्ट में पेश किए हैं। वहीं, अब ईडी इंदौर और भोपाल की मांग पर एमपी सरकार ने एक विशेष मंजूरी जारी कर दी है। इससे आरोपियों की आर्थिक कमर टूट जाएगी।

यह अधिकार मिलने के बाद ईडी की अटैचमेंट पावर बढ़ जाएगी। अभी ईडी को पंजीयन विभाग को पत्र लिखकर आरोपियों की संपत्तियों का विवरण मांगना पड़ता था। इसमें लंबा समय लगता था। कई बार आरोपी केस की जानकारी लगने पर इन संपत्तियों को दूसरों को बेचकर ठिकाने लगा देते थे। ईडी अब अपने दफ्तर में एक स्पेशल

टीम बनाएगा। यह टीम ई-संपदा सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेगी। इस सॉफ्टवेयर से पूरी मध्यप्रदेश में आरोपियों की संपत्तियों की जानकारी जुटाई जा सकेगी। इसके बाद, उन संपत्तियों को तुरंत अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अब आरोपियों की मुश्किलें बढ़ना तय है।

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में होती है संपत्ति अटैच-ईडी केस दर्ज होने के बाद जितनी राशि की आर्थिक अनियमितता (मनी लॉन्ड्रिंग) की गई है, उतनी लागत की संपत्तियों को तलाश कर अटैच करती है। ईडी के प्रारंभिक अटैचमेंट के बाद मामला ईडी न्यायाधिकरण में जाता है। फिर इस अटैचमेंट पर अंतिम मुहर लगती है। एक बार संपत्ति अटैच हो जाने के बाद इसका छूटना बहुत मुश्किल होता है, जब तक कि आरोपी बाइज्जत बरी न हो जाए।

ईडी की थी खास मांग, मोहन सरकार ने मानी

ईडी ने हाल ही में मध्यप्रदेश सरकार के पंजीयन विभाग से विशेष मंजूरी मांगी थी। इसमें मांग की गई थी कि उन्हें पंजीयन विभाग के ई-संपदा सॉफ्टवेयर का लॉगइन और पासवर्ड दिया जाए। साथ ही यह अधिकार भी दिए जाएं कि वे किसी की भी संपत्तियों को यहां से सर्च कर सकें। इससे ईडी इन संपत्तियों की जानकारी जुटाकर तेजी से उन्हें अटैच कर सकेगी। इस पर विचार करने के बाद आखिरकार पंजीयन विभाग ने इसकी मंजूरी ईडी को दे दी है।

मंत्री विजय शाह बोले-

मीडिया वाले मुझसे जलते हैं

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

खंडवा ● जनजातीय कार्य विभाग मंत्री विजय शाह ने कहा है कि मीडिया वाले उनसे जलते हैं। शाह ने यह बात गुरुवार को खंडवा मेडिकल कॉलेज में फॉरेंसिक साइंस पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में कही। मंत्री शाह बतौर मुख्य अतिथि यहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मेडिकल स्टूडेंट के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का जिक्र किया। बताया कि उनके विभाग ने इस साल 14 बच्चों की फीस चुकाई है। इनमें से प्रत्येक को 37-37 लाख रुपए दिए गए हैं।

मंत्री ने कार्यक्रम के दौरान मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर तंज भी कसा। जब डीन डॉ. संजय दादू ने कहा कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल के लिए आईटीआई कॉलेज के पीछे 14 एकड़ जमीन आवंटित है लेकिन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत नहीं हो पाया है। इस पर मंत्री शाह ने कहा- आपने 6 साल बाद जाकर इस डाकिये को बुलाया है। अब यह डाकिया आपकी मांग को सरकार तक भिजवाएगा। इस कॉलेज का नामकरण पूर्व सांसद नंदकुमार सिंह चौहान के नाम से है। मैं बता दूं कि इस उपलब्धि में मेरी भी बड़ी भूमिका थी। कॉन्फ्रेंस में मेडिकल स्टूडेंट्स ने समस्या रखी कि उन्हें अस्पताल जाने के लिए ऑटो या रिक्शे का सहारा लेना पड़ता है। इस पर मंत्री शाह ने हरसूद के सरकारी कॉलेज का जिक्र किया। कहा- मैंने वहां कॉलेज स्टूडेंट की सुविधा के लिए चार बसें दिलाई हैं। आपको भी इसी मार्च महीने तक एक बस दिला दूंगा। उऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शाह के खिलाफ अभियोजन पर स्वीकृति देने के लिए सरकार को दो हफ्ते का वक्त दिया है। कानूनी जानकारों की मानें तो विजय शाह के इस केस का ट्रायल इंदौर में एमपी-एमएलए कोर्ट में शुरू किया जा सकता है।

आयुष्मान के जीएम और सीईओ के पीए सस्पेंड

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

भोपाल ● मध्यप्रदेश आयुष्मान भारत योजना में बड़े भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद सरकार ने कार्रवाई की है। आयुष्मान विभाग के सीईओ योगेश भरसट के पीए छोटेलाल सिंह और विभाग के महाप्रबंधक (ऑपरेशनल) इंद्रजीत सिकरवार को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं आयुष्मान मित्र संदीप सिंह की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। जांच में सामने आया था कि किस तरह आयुष्मान योजना पर मेडिकल माफिया का कब्जा है। कई इम्पैनल्ड अस्पतालों में नियमों को ताक पर रखकर किराए के स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिखाए जा रहे थे और पूरे सिस्टम को मिलीभगत से चलाया जा रहा था।

इस सनसनीखेज खुलासे के बाद सरकार हरकत में आई और पूरे मामले को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की। पीए छोटेलाल सिंह और महाप्रबंधक इंद्रजीत सिकरवार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया, जबकि आयुष्मान मित्र संदीप सिंह की सेवाएं समाप्त कर दी गईं। एमपी में केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान योजना मेडिकल माफिया के कब्जे में है। एक शख्स के नाम पर कई अस्पतालों का संचालन हो रहा है। योजना में अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल डॉक्टरों को किराए पर रखते हैं। एमपी के किसी भी प्राइवेट अस्पताल को आयुष्मान योजना में इमपेनल्ड कराना है तो आयुष्मान विभाग के अफसर 10 लाख रुपए लेते हैं। इनमें सभी का हिस्सा बंटा होता है। अफसरों के पास सबसे ज्यादा हिस्सा पहुंचता है।

कोर्ट में सीएमएचओ बोले

जांच रिपोर्ट से वे स्वयं संतुष्ट नहीं शहर में संचालित अवैध हॉस्पिटलों पर हाईकोर्ट सख्त

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● शहर में संचालित अवैध हॉस्पिटलों को लेकर बुधवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगल पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक जांच रिपोर्ट पेश नहीं किए जाने पर अदालत ने नाराजगी जताई।

स्वास्थ्य विभाग की जांच पर उठे सवाल

मामले में सीएमएचओ माधव हासानी स्वयं अदालत में उपस्थित हुए। उन्होंने न्यायालय को बताया कि अवैध हॉस्पिटलों की जांच के लिए उनके स्तर पर आठ सदस्यीय समिति गठित की गई थी। सीएमएचओ ने अदालत को यह भी बताया कि समिति द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से वे स्वयं संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जांच में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को नजरअंदाज किया गया है। इस कारण समिति के सदस्यों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, उन्होंने अदालत से विस्तृत और संतोषजनक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का और समय मांगा। याचिकाकर्ता चर्चित शास्त्री की ओर से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल, जयेश गुरनानी और आदित रघुवंशी ने कोर्ट को अवगत कराया कि अदालत के पूर्व आदेश के बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच में जानबूझकर देरी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई हॉस्पिटल संचालकों ने कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर अस्पताल संचालन की अनुमति प्राप्त कर रखी है और प्रशासन इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दो सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा।

न्यूज ब्रीफ

आग लगने से पेट्रोल पंप कर्मचारी की मौत

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में शुक्रवार अलसुबह एक घर में आग लगने से 45 वर्षीय व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान राकेश शर्मा के रूप में हुई है, जो शुक्ला ब्रदर्स पेट्रोल पंप में कर्मचारी था। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चला है। पुलिस के अनुसार घटना रेवती रेंज इलाके की है। सुबह आसपास के लोगों ने राकेश शर्मा के घर से धुआं निकलते देखा। मोहल्ले के लोग पानी डालकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक राकेश की मौत हो चुकी थी। उसका शव घर के अंदर जली हुई अवस्था में मिला। राकेश के पिता ओंकार शर्मा ने बताया कि राकेश गुरुवार रात अस्पताल से घर लौटे थे। उनके बड़े बेटे का उसी रात एक्टिवा से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसके पैर में फ्रैक्चर आया था। रात में राकेश अस्पताल में बेटे के पास थे और देर रात घर आए थे। अस्पताल में भर्ती बेटे के पास दो बच्चे और मां थी। जबकि एक बेटा दादा के घर पर था। बाणगंगा पुलिस के मुताबिक मौके से गैस सिलेंडर की नली जली हुई अवस्था में मिली है। आशंका जताई जा रही है कि संभवत: सुबह चाय बनाने के दौरान गैस चालू करते समय आग लगी हो, हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

आगामी गाईडलाईन वर्ष 2026-27 में नवीन लोकेशन जोड़े जाने हेतु आवेदन आमंत्रित

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● आगामी वित्तीय वर्ष की गाईडलाईन वर्ष 2026-27 तैयार किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। वरिष्ठ जिला पंजीयक एवं संयोजक जिला मूल्यांकन समिति इंदौर श्रीमती मंजूलता पटेल ने बताया कि गाईडलाईन वर्ष 2026-27 में नवीन लोकेशन जोड़े जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। आगामी गाईडलाईन वर्ष 2026-27 में नवीन लोकेशन जोड़े जाने हेतु आवेदन मय समस्त अनुमतियों (टीएनसी नक्शा, रेरा आदि) सहित संबंधित कार्यालय वरिष्ठ जिला पंजीयक/जिला पंजीयक, जिला इंदौर-1, 2, 3 एवं 4 में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

डॉ. ए.के. द्विवेदी को मिली राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● चिकित्सा एवं आयुष क्षेत्र में इंदौर का नाम एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित हुआ है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने शहर के वरिष्ठ होम्योपैथी चिकित्सक डॉ. ए.के. द्विवेदी को शिलांग (मेघालय) स्थित पूर्वोत्तर आयुर्वेद एवं होम्योपैथी संस्थान की प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सलाहकार समिति में बतौर सदस्य (होम्योपैथी विशेषज्ञ) नामित किया है। संस्थान द्वारा 23 जनवरी 2026 को जारी आधिकारिक पत्र के अनुसार, आयुष मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में डॉ. द्विवेदी को अगले तीन वर्षों के लिए समिति का सदस्य मनोनीत किया गया है। उल्लेखनीय है कि ह्श्वद्ध॥, भारत सरकार के अधीन पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र स्वायत्त आयुष संस्थान है, जहाँ एक ही परिसर में आयुर्वेद और होम्योपैथी की उच्च शिक्षा, शोध गतिविधियाँ तथा चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध हैं।

पुल-पुलिया के नीचे स्थित बोगदे के लिए बनाए पॉलिसी-महापौर

प्रमुख सड़कें और फुटपाथ होंगे अतिक्रमण से मुक्त

महापौर ने यातायात और उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक ली

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने गुरुवार को निगम मुख्यालय स्थित महापौर सभाकक्ष में यातायात विभाग एवं उद्यान विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली गई। बैठक के दौरान महापौर भार्गव ने यातायात एवं उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली की विस्तार से समीक्षा करते हुए शहर को सुव्यवस्थित, सुंदर एवं अतिक्रमणमुक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। महापौर द्वारा शहर के चिन्हित प्रमुख मार्गों के फुटपाथों को अतिक्रमणमुक्त कर 'आदर्श मार्ग' के रूप में विकसित करने हेतु निर्देश दिए गए।

अवैध बोडर्डों और होर्डिंग्स पर हो कठोर कार्रवाई: इसके अंतर्गत एयरपोर्ट से बड़ा गणपति, बड़ा गणपति से एमजी रोड होते हुए पलासिया तक तथा बंगाली चौराहा से तिलक नगर चौराहा तक की सड़कों के फुटपाथों को अतिक्रमणमुक्त करने के लिए यातायात विभाग एवं रिमूव्हल विभाग को संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। महापौर ने शहर में मार्गों, चौराहों, पुलों एवं उद्यानों के नामकरण के पश्चात संबंधित सूचना बोर्ड शीघ्र लगाने के निर्देश दिए। साथ ही जिन संस्थाओं को

शहर के मिडियन, डिवाइडर, रोटरी एवं उद्यान गोद दिए गए हैं, उनके साथ आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर कार्य शीघ्र प्रारंभकराने के निर्देश भी दिए गए। इसके अतिरिक्त बिना अनुमति लगाए गए बोर्डों एवं होर्डिंग्स पर नियमानुसार कठोर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मधु मिलन चौराहे के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों हेतु तैयार किए गए प्लान की जानकारी भी ली गई। इसके साथ ही शहर के पुल-पुलियों के नीचे स्थित बोगदों में खेलकूद गतिविधियां, बैठक स्थल एवं अन्य जनोपयोगी विकास कार्यों के लिए एक समग्र पॉलिसी एवं प्लान तैयार करने के संबंध में भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। यातायात विभाग की समीक्षा के दौरान शहर के चौराहों एवं सड़कों के नामकरण, चौराहों पर किए जा रहे सौंदर्गीकरण एवं विकास कार्य, पुल-पुलियों के नीचे बोगदों का वर्तमान उपयोग एवं आगामी कार्य योजना, डिवाइडरों की पेंटिंग की स्थिति, विभिन्न मुख्य मार्गों पर जेंट्री गेट की स्थिति, प्रमुख मागों एवं ब्रिज पर लगे संकेतक बोर्डों की स्थिति, की समीक्षा की।

योग शेड एवं ओपन जिम की वार्डवार ली जानकारी

उद्यान विभाग की समीक्षा के अंतर्गत निर्माणाधीन युरेशिया गार्डन, सिटी फॉरेस्ट की कार्य योजना एवं वर्तमान प्रगति, निगम की नर्सरियों की क्षमता, ग्रीन बेल्ट, सेंट्रल डिवाइडर एवं अन्य क्षेत्रों को गोद देने की स्थिति, योग शेड एवं ओपन जिम की वार्डवार जानकारी पर भी विस्तार से चर्चा की गई। महापौर भार्गव ने बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने, हरित क्षेत्र बढ़ाने एवं सौंदर्यीकरण कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किया जाए, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो सकें और इंदौर शहर की स्वच्छ एवं सुंदर पहचान और अधिक मजबूत हो। बैठक में अपर आयुक्त अभय राजनगांवकर, कार्यपालन यंत्री पीएस कुशवाह, शांतिलाल यादव सहित दोनों विभागों के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु समुदाय के सर्वेक्षणकर्ताओं का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद एवं विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु विभाग के संयुक्त तत्वावधान में परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, कार्यपालक निदेशक बकुल लाड के मार्गदर्शन में विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्धघुमन्तु परिवारों के चिन्हांकन परियोजना अंर्तगत इंदौर संभाग (इंदौर और धार जिला) के सर्वेक्षणकर्ताओं का संभाग स्तरीय प्रशिक्षण देवी अहिल्या विश्वविद्यालय परिसर, इन्दौर में संपन्न हुआ । उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 12जिलों में उक्त समुदाय के लिए किए जा रहे सर्वेक्षण कार्यक्रम में इंदौर संभाग के दो जिले इंदौर और धार सम्मिलित हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के शासी निकाय सदस्य विनोद मोहने, विशिष्ट अतिथि के रूप में जगदीश जी पाराशर, विभाग संयोजक, घुमंतु कार्य, इंदौर विभाग, अमिताभ श्रीवास्तव, परियोजना प्रभारी, अमित शाह, संभाग समन्वयक, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद सम्मिलित रहे।

भारत के भाव पर गर्व करना शिक्षा के मंदिरों से निकलना चाहिए-मंत्री परमार

ज्ञानसभा में मध्यप्रदेश के विकास के लिए शिक्षा पर हुआ मंथन

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मध्य प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा विषय पर आयोजित मध्यप्रदेश ज्ञान सभा का समापन उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के मुख्य अतिथ्य में सम्पन्न हुआ। अपने संबोधन में मंत्री परमार ने कहा कि ज्ञान सभा मप्र को दिशा देने की कोशिश के रूप में देखता हूं। भारत के भाव पर गर्व करना शिक्षा के मन्दिरों से निकलना चाहिए। गुलामी के भाव को बाहर करना है। 2020 शिक्षा नीति आने के बाद हमने अपने को पहचानना प्रारम्भकर दिया है। भारत ने ज्ञान के आधार पर दुनिया को जीता था। शक्ति का आधार भारत का ज्ञान है।

हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सर्व प्रथम क्रियान्वित किया है, इसमें डॉ. अतुल कोठारी का महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे विश्वास है कि 2047 तक कैसी शिक्षा होना चाहिए यह मंथन हुआ होगा। समापन कार्यक्रम में प्रो. अर्पण भारद्वाज, पुरुषोत्तमदास पसारी ने भी संबोधित किया। समापन कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव को इंडिया नहीं भारत का प्रयोग करने पर सम्मानित किया गया। समापन कार्यक्रम का संचालन डॉ. दिनेश दवे ने किया।

साढ़े पांच करोड़ की लागत से सांवेर में विकास कार्यों की सौगात मिली

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि सांवेर विधानसभा की 110 ग्राम पंचायतों में एक हजार करोड़ रूपये से भी ज्यादा राशि के विकास कार्य हो गए हैं। सांवेर में विकास के पंख लगे हैं, जिससे सभी वर्गों को लाभ हो रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सांवेर नये कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वर्तमान में मुख्यमंत्री द्वारा साढे पांच करोड़ रूपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगातें मिली है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ।

सांवेर विधानसभा में लगभग साढ़े पांच करोड़ रूपये की लागत से 30 से अधिक ग्राम पंचायतों में सामुदायिक भवन, आजीविका भवन, तालाब सौन्दर्यीकरण, सार्वजनिक पार्क, शेड निर्माण, शौचालय, श्मशान घाट, विद्यालयों में नवीन कक्ष, अनुसूचित जाति छात्रावासों में विभिन्न विकास कार्यों होंगे।

मंत्री सिलावट ने बताया कि सांवेर के ग्राम पंचायत धनखेडी, हरियाखेडी, बावलियाखुर्द, गारिया, कैलोदहाला, गारी पिपलिया में 90 लाख रूपये के सामुदायिक भवन बनाये जायेंगे, वहीं ग्राम पंचायत पंचडेरिया, बावलियाखेडी, जैतपुरा, टाकुन, कदवाली बुजुर्ग, बुढी बरलाई में 90 लाख रूपये के आजीविका भवन, ग्राम पंचायत पंचडेरिया, बसान्द्रा, माताबरोडी, मण्डोद, कदवाली बुजुर्ग, लसुडिया परमार, सुल्लाखेडी, झलारिया, बुरानाखेडी, कम्पेल, शिवनी में एक करोड़ दस लाख के तालाब सौन्दर्यीकरण के कार्य होंगे। ग्राम पंचायत चन्द्रावतीगंज, अजनोद, कछालिया और बुढी बरलाई में एक करोड़ रूपये के सार्वजनिक पार्कों का निर्माण होगा।

ग्राहक मिलन समारोह संपन्न

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● इंदौर क्लॉथ मार्केट को. ऑप. बैंक लिमिटेड, इंदौर द्वारा आयोजित ग्राहक मिलन समारोह भव्य रूप से संपन्न हुआ । समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्जवलन एवं सरस्वती वंदन से प्रारंभ हुआ, जिसमे बैंक के सभी पदाधिकारी, संचालकगण एवं असंख्य व्यापारीगण उपस्थित रहे । समारोह को संबोधित करते हुए बैंक अध्यक्ष अमरीश दम्मानी द्वारा बताया की बैंक सतत रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक, सहकारिता विभाग के मापदंडो को पूर्ण करते हुए व्यापारीगण एवं सदस्यों के हित में नित नवीन कार्य कर रही है । बैंक स्वयं के निजी भवन हुकुमचंद मार्ग (कपडा मार्केट) से 05 शाखाओ के रूप में संचालित है। बैंक की पंचम शाखा केसरबाग रोड स्थित न्यू देवी अहिल्या क्लॉथ मार्केट पर प्रारंभ होकर कार्यरत है।

विधायक व एमआईसी सदस्य द्वारा सड़क के लिए भूमिपूजन

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मध्यप्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत न्यू साइंस कॉलेज से चन्द्रशेखर आजाद हॉस्टल तक प्रस्तावित सी.सी. मार्ग निर्माण कार्य का भूमिपूजन समारोह आज गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। यह मार्ग 750 मीटर लंबा एवं 5.50 मीटर चौड़ा होगा, जिसकी अनुमानित लागत 136.79 लाख रुपए है।

इस महत्वपूर्ण विकास कार्य का भूमिपूजन विधायक, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-3 गोलू शुक्ला एवं महापौर परिषद् (एमआईसी) सदस्य मनीष शर्मा (मामा) द्वारा विधिवत पूजन-अर्चन कर किया गया। विधायक इस अवसर पर गोलू शुक्ला ने कहा कि क्षेत्र में आधारभूत

सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण उनकी प्राथमिकता है। उक्त मार्ग के निर्माण से विद्यार्थियों, स्थानीय रहवासियों एवं आम नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र के समग्र विकास को गति प्राप्त होगी। मनीष शर्मा (मामा) ने भी अपने विचार रखे।

आचार्य बालकृष्ण और 'वंदे भारत' फेम सुधांशु मणि आएंगे

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● रोटरी मंडल 3040 द्वारा अपने प्रतिष्ठित 42वें रोटरी मंडल अधिवेशन इंद्रधनुष का आयोजन 31 जनवरी और 1 फरवरी को ग्रैंड शेरेटन, इंदौर में किया जा रहा है। यह दो दिवसीय अधिवेशन रोटरी के मूल मंत्र सेवा, नेतृत्व और सामाजिक सरोकार को केंद्र में रखकर आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 25 राजस्व जिलों और गुजरात के 4 जिलों से लगभग 800 से 900 रोटेरियन सहभागिता कर रहे हैं। इस भव्य कार्यक्रम का संपादन जिला गवर्नर सुशील मल्होत्रा, फर्स्ट लेडी रूबी मल्होत्रा और कॉन्फ्रेंस चेयरमैन बृजेश अग्रवाल के सक्षम नेतृत्व में किया जा रहा है। रोटरी के पदाधिकारियों ने बताया कि इस अधिवेशन में देश और विदेश से अनेक प्रख्यात रोटरी लीडर्स और विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। अमेरिका से डॉ. रमेश गर्ग और डॉ. रीता गर्ग, यूके से पीडीजी विजय पटेल और नयना पटेल के साथ आरआईपीआर पीडीजी दिनेश मेहता सहित कई वरिष्ठ रोटेरियंस अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।

कार्मिकों के सघन प्रशिक्षण सत्रों से क्षमता वृद्धि के निर्देश

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री अनूप कुमार सिंह ने गुरुवार की शाम विभाग प्रमुखों की मिटिंग ली। उन्होंने कंपनी के सभी विभाग जैसे वाणिज्य, सतर्कता, आपूर्ति, क्रय, सुरक्षा, मानव संसाधन, मैंटेनेंस, विधि शाखा, परियोजना, कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी इत्यादि के कार्मिकों को सघन प्रशिक्षण देने के लिए फरवरी व आगामी माहों में विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि कार्मिकों में शासकीय योजनाओं का संचालन, तकनीकी विकास, उपभोक्ता सेवा संचालन, चुनौतियों से मुकाबले आदि की क्षमता का पर्याप्त विकास हो सके। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक प्रकाश सिंह चौहान समेत विभिन्न विभागाध्यक्ष मौजूद थे।

फर्जी क्लेम का पर्दाफाश :पैर कटने के नाम पर 50 लाख का मुआवजा मांगने वाला केस खारिज, तीन साल बाद खुला सच

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● एक कथित सड़क हादसे में पैर गंवाने का दावा कर 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग करने वाले ट्रक ड्राइवर का क्लेम केस जिला कोर्ट ने खारिज कर दिया है। करीब तीन साल चली सुनवाई के बाद इंश्योरेंस कंपनी की सख्त जिरह और ठोस तथ्यों से यह मामला फर्जी साबित हो गया। कोर्ट ने माना कि दुर्घटना संदिग्ध है और पैर कटने का कारण किसी अन्य वजह से जुड़ा हो सकता है।

मामला ट्रक ड्राइवर जगदीश

पिता भेरू (22) निवासी सैलाना रतलाम का है। उसने 9 नवंबर 2023 को जिला न्यायालय में क्लेम केस दायर किया था। याचिका में कहा गया कि 7 जुलाई 2023 को वह राजस्थान के सन सिटी ट्रांसपोर्ट के मालिक मुकेश चौधरी का ट्राला लेकर देवास से बांसवाड़ा जा रहा था। इसी दौरान सरवन थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्राले ने उसके ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे उसका दायां पैर गंभीर रूप से घायल हुआ और इलाज के दौरान घुटने के ऊपर से उसे काटना पड़ा। ड्राइवर ने खुद को 15 हजार रुपए मासिक आय वाला बताते हुए स्थायी अपंगता के आधार पर 50 लाख रुपए मुआवजा ब्याज सहित देने की मांग की थी। इसके लिए ट्राले के मालिक, चालक और इंश्योरेंस कंपनी को पक्षकार बनाया गया। टक्कर मारने वाले ट्राले की ओर से इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता राजेश चौरसिया ने कोर्ट में तर्क रखा कि हादसा 7 जुलाई का बताया गया, लेकिन एफआईआर 15 दिन बाद 22 जुलाई 2023 को दर्ज हुई। जिस ट्रक को जगदीश खुद चला रहा था, उसे केस में पक्षकार ही नहीं बनाया गया। दोनों वाहन राजस्थान पासिंग हैं, जिससे मामला शुरू से ही संदेहास्पद है। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ड्राइवर जगदीश ने स्वीकार किया कि जिस ट्राले से टक्कर बताई गई और जिसे वह चला रहा था, दोनों का मालिक एक ही ट्रांसपोर्टर है। यहीं से पूरा मामला उजागर हो गया।

सात दिवसीय विशेष शिविर ग्राम जैतपुरा में संपन्न

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● शासकीय महाविद्यालय सांवेर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का सात दिवसीय विशेष शिविर ग्राम जैतपुरा में 22 जनवरी से 28 जनवरी तक आयोजित हुआ। जिसमें शिविरार्थियों ने ग्रामवासियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने हेतु प्रति दिवस प्रभात फेरी निकाल कर, योग व व्यायाम कर स्वास्थ्य के प्रति तथा रैली निकाल कर पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। परियोजना कार्य के अंतर्गत शिविरार्थियों ने शा प्रा वि जैतपुरा में अनावश्यक घास निकाल कर, पाउच पन्नी पालीथिन बीन कर एवं झाडू लगा कर, क्यारी का निर्माण कर, ग्राम के हनुमान मंदिर से राम मंदिर तक सड़क पर झाडू लगा कर, मुख्य सड़क किनारे चौक नाली की सफाई कर श्रमदान कार्य किया। बौध्दिक कार्यक्रम में शिविरार्थियों को श्री गोरधन बोरवाल , पूर्व सरपंच श्री पूना जी परमार ने समाज सेवा हेतु प्रेरित किया।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
इंदौर, शुक्रवार 30 जनवरी 2026

न्यूज ब्रीफ

महेश बंसल की पुस्तक 'पुष्प गंगा' ने रचा दोहरा रिकॉर्ड

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● प्रकृति-प्रेम और टैरेस गार्डनिंग को समर्पित व्यक्तित्व मनीष बाग इंदौर के पर्यावरणविद महेश बंसल की 14 दिसम्बर 2025 को प्रकाशित कॉफी टेबल बुक 'पुष्प गंगा : मेरी बगिया के 101 फूल' ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। यह पहला मौका है जब 'पुष्प गंगा' ने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तथा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एकसाथ अपनी जगह बनाई है। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यह कीर्तिमान 'निजी टैरेस (रूफटॉप) गार्डन में समयक्रम से खिले फूलों पर आधारित विश्व की पहली कॉफी टेबल बुक' श्रेणी में दर्ज हुआ है जबकि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में यह पुस्तक 'एक व्यक्ति द्वारा चित्रों सहित अधिकतम फूलों का विवरण प्रस्तुत करने वाली पुस्तक' श्रेणी में दर्ज हुई है।

धरावरा धाम में मानस सम्मेलन एवं सात दिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ, पं. नागर आएंगे

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● धार रोड स्थित प्राचीन आस्था केंद्र धरावरा धाम पर 22 से 28 फरवरी तक आश्रम के संस्थापक साकेतवासी महंत घनश्याम दास महाराज की 17 वीं पुण्यतिथि के प्रसंग पर श्री मानस सम्मलेन एवं भागवत ज्ञान यज्ञ का दिव्य अनुष्ठान होगा। शाजापुर जिले के प्रख्यात भागवत मनीषी पं. ब्रजकिशोर नागर धरावरा धाम भक्त मंडल न्यास की मेजबानी में यहाँ प्रतिदिन भागवत कथामृत का रसपान कराएंगे। अनुष्ठान में आसपास के 25 गांवों के श्रद्धालुओं की भागीदारी रहेगी। गुरुवार को धरावरा धाम आश्रम पर पीठाधीश्वर महंत शुकदेव दास महाराज के सानिध्य में भक्त मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मानस सम्मेलन, भागवत ज्ञान यज्ञ, महाप्रसादी एवं अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया।

अग्रसेन महासभा के सामूहिक विवाह समारोह के लिए अनेक समितियां गठित

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● श्री अग्रसेन महासभा द्वारा 13-14 फरवरी को होने वाले सामूहिक विवाह समारोह की तैयारियों के लिए आयोजित बैठक में विभिन्न समितियों का गठन किया गया। सामूहिक विवाह के लिए सभी तैयारियां 'घर जैसी शादी' की तरह की जा रही है। महासभा परिवार की महिलाऐं और नवयुगलों के रिश्तेदार मिलकर 13 फरवरी को महिला संगीत के साथ इस महोत्सव का शुभारम्भ करेंगे। सम्पूर्ण विवाहोत्सव बायपास सहित महासभा के मांगलिक भवन पर सम्पन्न होंगे। दोनों पक्षों के मेहमानों को मांगलिक भवन के वातानुकूलित कक्षों में ठहराया जाएगा।

आम बजट से प्रदेश की उम्मीदें, कितनी पूरी होंगी

भोपाल (एजेंसी) ● केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करने वाली हैं, लेकिन इससे पहले राज्यों की उम्मीदों और मांगों का दौर तेज हो गया है। लगभग साढ़े चार लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दबी मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर केंद्र सरकार के सामने अपनी वित्तीय जरूरतों की एक लंबी सूची रखी है। इसमें सबसे प्रमुख मांग 2028 में उज्जैन में होने वाले विश्व प्रसिद्ध सिंहस्थ के लिए 20,000 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज है। इसके साथ ही राज्य ने अपनी कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने और जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के हजारों करोड़ के बकाया को चुकाने की गुहार भी लगाई है।

सिंहस्थ की तैयारीः 20 हजार करोड़ की दरकार

2028 में उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और राज्य के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। इसकी तैयारियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के मुताबिक राज्य सरकार ने उज्जैन और उसके आसपास के क्षेत्रों में सड़कों, घाटों, पुल-पुलिया, अस्पतालों और यात्रियों के लिए ठहरने के स्थलों का निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। वर्तमान में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के बुनियादी ढांचे के काम स्वीकृत किए जा चुके हैं और वे प्रगति पर हैं।

आदिवासी छात्रों की स्कॉलरशिप

इसी तरह जनजातीय छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में भी केंद्र पर 2018-19 से लेकर 2024-25 तक 564 करोड़ रुपए बकाया हैं। राज्य सरकार यह स्कॉलरशिप छात्रों को अपने खजाने से दे चुकी है। अब केंद्र से इस राशि के भुगतान का इंतजार कर रही है।

राज्य के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य की जरूरतों का एक विस्तृत ड्राफ्ट सौंपा। यह ड्राफ्ट न केवल राज्य की वित्तीय चुनौतियों को दर्शाता है, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए उसकी विकास योजनाओं की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है।

16वें वित्त आयोग से बंधी उम्मीदें

मध्य प्रदेश की वित्तीय उम्मीदें काफी हद तक 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर टिकी हुई हैं। वर्तमान में केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी 7.85% है, जिससे प्रदेश को लगभग 1 लाख 11 हजार करोड़ रुपए मिलते हैं। राज्य सरकार ने अपनी बढ़ती जरूरतों और भौगोलिक विस्तार का हवाला देते हुए इस हिस्सेदारी में 10% बढ़ोतरी की मांग की है। अगर केंद्र इस मांग को स्वीकार करता है तो मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों से लगभग 1.22 लाख करोड़ रुपए मिल सकते हैं।

कर्ज का बढ़ता बोझ और सीमा बढ़ाने की गुहार

मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति कर्ज के बढ़ते बोझ से जूझ रही है। 1 अप्रैल 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक, यानी केवल 9 महीनों में मोहन सरकार 53,100 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। राज्य पर कुल कर्ज का आंकड़ा साढ़े चार लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है। इस स्थिति के बावजूद सरकार ने केंद्र से कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने की मांग की है।

सवर्ण सेना द्वारा रैली निकालकर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सोपा

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● अभय अग्रवाल अग्रवाल सेना ने बताया कि आज सवर्ण सेना के द्वारा भारी जनसमूह के साथ जॉइंट कमिश्नर डीएस रणदा को ज्ञापन देते हुए उक्त बिंदुओं को संज्ञान में लाया गया। जिसके बाद उन्होंने सम्मिलित सवर्ण सेना के सदस्यों को संबोधित करते हुए उक्त ज्ञापन को प्रधानमंत्री भारत सरकार को प्रेषित करने का वचन दिया। प्रदर्शन के दौरान हिंदू एकता जिंदाबाद, यूजीसी काला कानून वापस लो, जय जय सियाराम के नारे लगे रैली जब गांधी हॉल से प्रारंभ होकर कमिश्नर कार्यालय पहुंची तब पुलिस द्वारा हाथापाई की गई सेना के लोग बैरिकेट्स पार करके जॉइंट कमिश्नर साहब को मान्य प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा और मांग करी की जल्द ही इस विषय का निराकरण किया जाना चाहिए। जॉइंट कमिश्नर श्री डी एस रंदा ने कहा कि यह ज्ञापन केंद्र सरकार तक पहुंचा दिया जाएगा। तभी सवर्ण सेना के कार्यकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा

दिए गए स्टे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेखित किया है। कि ऐसा कानून का दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया है अभी वर्तमान में यूजीसी के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालय में महाविद्यालय में यूजीसी का 2012 का नियम ही चलेगा कार्यकर्ताओं द्वारा रीगल चौराहे पर मिठाई बाट कर जश्न मनाया गया इस अवसर पर माँ करणी सेना से-बाला ठाकुर, गोलू ठाकुर, यादवेंद्र सिंह, जितेंद्र पवार, शैलेन्द्र सिंह चंदेल, शिशुपाल सिंह, ठाकुर जगदीश सिंह, ईश्वर सिंह राठौड़ तथा कायस्थ समाज से राकेश श्रीवास्तव, वीना श्रीवास्तव, महावीर श्रीवास्तव, प्रदीप भटनागर, महेंद्र श्रीवास्तव, रत्नेश श्रीवास्तव,सुशील श्रीवास्तव, किरण भटनागर, निर्गुण श्रीवास्तव, शैलेन्द्र निगम,चंद्रमोहन श्रीवास्तव, अर्पित निगम, रमेश श्रीवताव, सतीश श्रीवास्तव, अमित श्रीवास्तव तथा अन्य कायस्थजन उपस्थित थे।

परसरामपुरिया एकेडमी के बच्चों ने लिया जंक फुड से दूरी बनाए रखने का संकल्प

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● राजमोहल्ला स्थित परसरामपुरिया एकेडमी का वार्षिकोत्सव साहित्यकार महेंद्र कुमार सांघी के मुख्य आतिथ्य एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त समाजसेवी रामदास गोयल की अध्यक्षता में विद्यालय परिसर में सम्पन्न हुआ। सरस्वती वन्दना के साथ प्रारंभ हुए इस आयोजन में ट्रस्टी डॉ. लोकेश जोशी, सचिव कुणाल मिश्रा, डॉ. निर्मल महाजन ने भी अपने प्रेरक विचार रखे और अतिथियों के साथ विद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। मुख्य अतिथि सांघी ने बच्चों को जंक फुड का सेवन नहीं करने का संकल्प दिलाया और जंक फुड से होने वाले नुकसान भी बताए। बच्चों ने दुर्गास्त्रोत, राधा कृष्ण गीत पर नृत्य, पर्यावरण की रक्षा में आदिवासियों के योगदान, शिव

नृत्य, भगोरिया उत्सव सहित अनेक रंगारंग प्रस्तुतियों से मेहमानों का मन मोह लिया। दुर्गास्त्रोत पर आधारित 'ऐ गिरि नंदिनी.....' और लता मंगेशकरजी के गाए गीत 'सर पर हिमालय का छत्र है...' को खूब तालियाँ मिली। विद्यालय के बच्चों ने विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पर आधारित प्रदर्शनी के साथ ही आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स प्रदर्शनी में देश के 51 शक्तिपीठों एवं प्रमुख मंदिरों की प्रतिकृतियाँ भी बनाई, जिनका अवलोकन कर मेहमानों ने खुलेमन से प्रशंसा की। संचालन श्रीमती मनीषा वर्मा एवं दीपा अग्रवाल ने किया। अंत में आभार माना प्राचार्य श्रीमती रंजना कोटिया ने।

अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कॅरियर का चुनाव करें

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● जिंदगी अनमोल है , आवश्यकता इस बात की है कि इसे नियोजित कर अपने सपनों को साकार किया जाए। जो विद्यार्थी अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों का चुनाव करते है, वे केवल शिक्षा जगत में ही नहीं अपने जीवन के कार्यक्षेत्र में नई ऊँचाई को छूते देखे गए हैं। वे कार्य के दौरान न तो थकते है न असफल होते है । ऐसे लोग अपने कार्यक्षेत्र में नीत नवीन सफल प्रयोग कर समाज के सामने अपनी पहचान बनाते है।उक्त विचार शासकीय नेहरू नगर कन्या उमावि इंदौर में आयोजित कॅरियर काउंसलिंग कार्यशाला में कैरियर काउंसलर दीपक हलवे ने रखे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि दैनिक समाचार पत्रों को अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रम का ही हिस्सा माने। समाचार पत्र आपके निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने का रास्ता दिखाते है।

खजराना क्षेत्र की बिजली सब स्टेशन क्षमता विस्तारित

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ●मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह के निर्देश पर शहर वृत्त अंतर्गत बिजली वितरण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। शहर अधीक्षण यंत्री डीके गाठे ने बताया कि गुरूवार को पूर्व शहर संभाग के तहत खजराना स्थित 33/11 केवी सब स्टेशन की क्षमता का विस्तार किया गया। अधीक्षण यंत्री ने बताया कि पहले इस ग्रिड की क्षमता 13 एमवीए थी। यहां करीब 50 लाख की लागत का नया पावर ट्रांसफार्मर लगाकर क्षमता अब 18 एमवीए कर दी गई है। इससे खजराना, मनीषपुरी समेत कुल 8 कॉलोनी के बिजली उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। अधीक्षण यंत्री ने बताया कि यह विस्तार गर्मी में मांग बढ़ने पर गुणवत्ता से आपूर्ति करने के लिए किया गया है।

CHANGE OF NAME

My old name is Kuldeep Kumar Tiwari S/O Vidya Sagar Tiwari, I have changed my name and my new name is Kuldeep Tiwari S/O Vidhya Sagar Tiwari, I will be known by my new name Kuldeep Tiwari

Address
51,main road,
Jagdish nagar,
Indore (MP) 452001

जाहिर सूचना

सर्व साधारण को एतद् द्वारा सूचित करने में आता है कि मैं 7-बी, कमला नेहरू नगर, इन्दौर (म.प्र.) का निवासी होकर पूर्व में मुझे विजय माली पिता सत्यनारायण के नाम से जाना व पहचाना जाता था तथा मेरे दस्तावेजो में यही नाम उल्लेखित था वर्तमान में मेरे द्वारा मेरा नाम विजय माली पिता सत्यनारायण से परिवर्तित होकर विजय योगी पिता सत्यनारायण हो गया है तथा यही नाम मेरे द्वारा मेरे पहचान संबंधित दस्तावेजो में दर्ज करवा लिया गया है। अब भविष्य में मुझे विजय योगी पिता सत्यनाराण के नाम से ही जाना व पहचाना जावे। सो विदित होवे।

सांध्य दैनिक
इंदौर संकेत
आपकी बात, इंदौर संकेत के साथ

डिजिटल रूप से लाखों पाठकों के साथ अपना नियमित संपर्क बनाते हुए दैनिक इंदौर संकेत अब एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आप भी अपने संस्थान, उत्पाद, संस्था का प्रचार-प्रसार दैनिक इंदौर संकेत के माध्यम से सकते हैं। इसके तहत आप चाहे प्रापर्टी व्यवसाय से जुड़े हैं या कोई बधाई संदेश देना है या जन्मदिन की शुभकामनाएं हो या कोई अन्य कैटेगरी में विज्ञापन देना चाहते हैं तो न्यूनतम दर पर प्रकाशित करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। दैनिक इंदौर संकेत संवेदनापूर्ण संदेशों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। इसीलिए इस समाचार पत्र में शोक संदेश नि:शुल्क प्रकाशित किए जाएंगे।

कार्यालय का पता
5/6, राज मोहल्ला, महेश नगर,
गुरुद्वारे के सामने, इंदौर
संपर्क: 94250-64357,94245-83000

सच्चा मित्र वही जो हमें अपनी कमियों एवं कमजोरियों से आगाह करें - पं. शास्त्री

दैनिक इंदौर संकेत

इंदौर ● सच्चा मित्र वही होता है जो अपनी कमियों एवं कमजोरियों से हमें आगाह करें। मित्रता में छल-कपट नहीं होना चाहिए। आज मैत्री को नए संदर्भों में परिभाषित करने की जरूरत है। राजा-प्रजा के बीच निष्कपट मैत्री का भाव होना चाहिए। कथा में हम तो बैठ लिए, अब कथा को भी अपने अंतर्मन में बैठाने की जरूरत है। जूनी इंदौर मुक्ति धाम सेवा समिति के तत्वावधान में चल रहे भागवत ज्ञानयज्ञ में भागवताचार्य पं. श्याम सुंदर शास्त्री ने गुरुवार को उक्त प्रेरक विचार व्यक्त किए। कथा शुभारम्भ के पूर्व समाजसेवी प्रमोद रामेश्वर खटोड, राहुल सोनकर, ओमप्रकाश मालू, प्रेम चौहान, ओमप्रकाश सोनकर, रणजीत सोनकर पहलवान, राजेश जोशी, जगदीश पांचाल सहित अनेक भक्तों ने व्यास पीठ का पूजन किया। संयोजक अशोक सारडा एवं

राजेश जोशी ने बताया कि जूनी इंदौर मोक्ष धाम पर सम्पन्न हुई इस भागवत कथा का समापन गुरुवार को लगभग 2 हजार भक्तों के लिए महाप्रसादी के साथ सम्पन्न हुआ। उत्सव के लाभार्थी प्रमोद खटोड एवं राहुल सोनकर मित्र मंडल के सदस्यों ने पूरे मनोयोग से सहयोग प्रदान किया। कथा के दौरान भगवान एवं उनके बाल सखा सुदामा की मित्रता का जीवंत उत्सव भी मनाया गया। कृष्ण-सुदामा मिलन का हृदयस्पर्शी चित्रण सुनकर अनेक आंखे छलछला उठी। इस दौरान मोक्ष धाम परिसर स्थित महामृत्युंजय मंदिर पर पं. राजेश तिवारी एवं अन्य विद्वानों द्वारा किए जा रहे भागवत के मूलपारायण का भी आज समापन हो गया। समापन प्रसंग पर मोक्ष धाम परिसर में भागवतजी की शोभा यात्रा भी निकाली गई। समापन अवसर पर जूनी इंदौर मोक्ष धाम पर पहली बार भंडारे का आयोजन भी सम्पन्न हुआ। शुक्रवार 30 जनवरी को सुबह 9 बजे मोक्ष धाम पर रखी हुई दिवंगतों की अस्थियों का शास्त्रोक्त विधि से पूजन कर नर्मदा में विसर्जन के लिए खेड़ीघाट के लिए विदा किया जाएगा।

सम्पादकीय

6.8 से 7.2 फीसदी की ग्रोथ, लेकिन राह आसान नहीं, आर्थिक समीक्षा ने बजट से पहले उठाए बड़े सवाल

आर्थिक समीक्षा 2026-27 में जीडीपी वृद्धि, रुपये की स्थिति, वैश्विक चुनौतियों, कृषि, महंगाई और लोकलुभावन योजनाओं पर सरकार के संकेतों का विश्लेषण। हर साल संसद में पेश होने वाली आर्थिक समीक्षा आमतौर पर इस बात का ब्योरा होती है कि पिछले बजट में देश की अर्थव्यवस्था और अन्य मोर्चे पर सुधार के लिए जो वादे किए गए थे, वे किस हद तक पूरे किए जा सके। यह इसका भी संकेत होता है कि अगले वित्त वर्ष में सरकार के आर्थिक फैसलों में किन मसलों को प्राथमिकता मिल सकती है। इस लिहाज से देखें, तो वित्त मंत्री ने जो आर्थिक समीक्षा पेश की है, वह देश की परिस्थितियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खड़ी हो रही आर्थिक चुनौतियों के बीच उम्मीद जगाती है, लेकिन यह आने वाले वक्त के जोखिमों के प्रति आगाह भी करती है। समीक्षा में वित्त वर्ष 2026-27 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.8 फीसद से 7.2 फीसद के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। विदेशी पूंजी प्रवाह में कमी के कारण रुपए पर प्रतिकूल असर और बीते वर्ष भारतीय मुद्रा में कमजोरी के बावजूद यह अनुमान अर्थव्यवस्था में स्थिरता का संकेत देता है। हालांकि समीक्षा में विकसित भारत और वैश्विक प्रभाव का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से मजबूत और स्थिर मुद्रा को एक स्वाभाविक जरूरत बताने के समांतर रुपए के मूल्य में गिरावट को हानिकारक नहीं माना गया, क्योंकि यह भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी शुल्क में इजाफे के असर को कुछ हद तक कम करता है। दूसरी ओर, यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर यह उम्मीद जताई गई है कि यह भारत की विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक, निर्यात और रणनीतिक क्षमता को मजबूत करेगा। समीक्षा के मुताबिक, अनिश्चित वैश्विक माहौल में भारत को घरेलू वृद्धि को प्राथमिकता देने की जरूरत है और इसके लिए वित्तीय सुरक्षा उपायों और नकदी पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जाहिर है, वैश्विक आर्थिक मोर्चे पर तेजी से बदलते समीकरण और भू-राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनजर भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए अपने हितों के अनुकूल उपाय करने होंगे। आर्थिक समीक्षा में नवोन्मेष और वैश्विक पहलकदमियों को कमजोर किए बिना दक्षता और स्वदेशी को अपनाने का आह्वान किया गया है, जो निश्चित रूप से आत्मनिर्भरता की संभावनाओं को मजबूत करेगा।

स्त्री का मूल्य अब कोख नहीं, उसके विचार हैं नई पीढ़ी, नया साहस, मातृत्व का नया विमर्श

जिस दिन कोई युवती यह कह देती है- 'मुझे माँ नहीं बनना', उस दिन समाज की सबसे सुरक्षित मान्यता असुरक्षित हो जाती है। यह वाक्य भावनाओं से नहीं, चेतना से पैदा होता है, इसलिए डराता है। यह उस अदृश्य स्क्रिप्ट को जला देता है, जिसमें स्त्री का भविष्य जन्म के साथ ही लिख दिया गया था। लोग चौंकते इसलिए हैं कि पहली बार स्त्री अपनी देह को विरासत नहीं, निर्णय का क्षेत्र घोषित करती है। यह इंकार न तो आक्रामक है, न ही विद्रोही दिखता है, फिर भी यह सबसे गहरी बगावत है क्योंकि यह बिना चीखे, बिना अनुमति माँगे, व्यवस्था के केंद्र में सीधा सवाल खड़ा कर देता है।

माँ न बनने का साहस, समाज की आंखें खोलता है

सदियों से स्त्री को यह पाठ पढ़ाया गया कि उसका अस्तित्व स्वयं के लिए नहीं, दूसरों की जरूरतों के लिए है—पहले परिवार, फिर पति और अंततः संतान के लिए। मातृत्व को इतना ऊँचा उठाया गया कि उसके भार तले स्त्री की पहचान दबकर रह गई। उसे सिखाया गया कि त्याग उसका सौंदर्य है और सहनशीलता उसका स्वभाव। आज की बेटियाँ इसी शिक्षा को जाँच की निगाह से देख रही हैं। वे पूछ रही हैं—यदि त्याग ही स्त्री की नियति है, तो पुरुष की नियति क्या है? यह प्रश्न किसी एक भूमिका पर नहीं, बल्कि पूरी सामाजिक संरचना पर सीधा प्रहार करता है।

शिक्षा ने इन सवालों को भाषा दी है और चेतना ने उन्हें निडरता। आज की युवा महिलाएँ जीवन को केवल निभाने की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जीने का अधिकार मानती हैं। वे जानती हैं कि मातृत्व भावनाओं का उत्सव भी हो सकता है, लेकिन प्रायः यह अदृश्य श्रम, लगातार थकान और स्वयं से मिटते जाने की प्रक्रिया भी बन जाता है। वे साफ देखती हैं कि बराबरी के दावे संकट के समय सबसे पहले टूटते हैं। जब मातृत्व की कीमत एकतरफा वसूली जाए, तब उससे इंकार करना स्वार्थ नहीं, बल्कि न्याय की स्पष्ट माँग बन जाता है।

आर्थिक यथार्थ इस निर्णय को और ठोस बना देता है। आज का समय महँगा है, अनिश्चित है और अस्थिर है। एक बच्चे का पालन-पोषण अब केवल प्रेम का विस्तार नहीं, बल्कि वर्षों तक चलने वाला आर्थिक दबाव है। नौकरी छोड़ना, अवसर खोना और निर्भरता स्वीकार करना अब भी ज़्यादातर स्त्रियों के हिस्से आता है। युवा महिलाएँ इस गणित को भावनाओं से नहीं, विवेक से हल करती हैं। वे पूछती हैं—क्या मातृत्व का अर्थ आर्थिक असुरक्षा को स्थायी बनाना होना चाहिए? यह सवाल सुंदर नहीं, लेकिन सच है।

मानसिक स्वास्थ्य वह सच है जिसे सबसे लंबे समय तक दबाया गया। माँ को देवी बनाकर उसकी थकान को अदृश्य कर दिया गया। प्रसवोत्तर अवसाद, अकेलापन और हर हाल में 'अच्छी माँ' बने रहने का दबाव वर्षों तक मौन में छिपा रहा। नई पीढ़ी की महिलाएँ इस चुप्पी को तोड़ रही हैं। वे स्वीकार कर रही हैं कि हर स्त्री माँ बनने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होती, और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस है। वे साफ कहती हैं—यदि मातृत्व के नाम पर स्वयं को खोना पड़े, तो स्वयं को बचाना अधिक ज़रूरी है।

पर्यावरणीय चेतना ने इस बहस को निजी दायरे से बाहर निकालकर वैश्विक धरातल पर ला खड़ा किया है। जलवायु संकट, सिकुड़ते संसाधन और भविष्य की भयावह अनिश्चितता के बीच अनेक युवतियाँ यह कठोर प्रश्न उठा रही हैं कि क्या ऐसे संसार में बच्चे को जन्म देना नैतिक रूप से उचित है। उनके लिए माँ न बनना जिम्मेदारी से भागना नहीं, बल्कि उसे गंभीरता से लेना है। वे मातृत्व को केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि पृथ्वी पर पड़ने वाले उसके प्रभाव के संदर्भ में देखती हैं। यह दृष्टि भावनाओं से नहीं, विवेक से उपजी है, और शायद इसी कारण यह पारंपरिक सोच को असहज करती है।

समाज की प्रतिक्रिया आज भी कटु और दंडात्मक है। कहा जाता है कि वे अधूरी हैं, स्वार्थी हैं, या भविष्य में पछताएँगी। लेकिन ये आरोप स्त्री के नहीं, समाज के भय को उजागर करते हैं—उस भय को, जो उसे स्त्री की स्वायत्तता से लगता है। नई पीढ़ी की महिलाएँ अब स्पष्टीकरण नहीं देतीं। वे जानती हैं कि जीवन की पूर्णता किसी एक भूमिका में कैद नहीं होती। वे रिश्तों, सृजन, सामाजिक सहभागिता और आत्मसम्मान में भी जीवन का अर्थ तलाशती हैं। उनका आत्मविश्वास इसलिए चुभता है, क्योंकि यह नियंत्रण और आदेश की भाषा को सिरे से नकार देता है।

यह विमर्श मातृत्व के विरोध में नहीं, बल्कि उसके एकाधिकार के विरुद्ध खड़ा है। नई पीढ़ी माँ बनने की संभावना को नकार नहीं रही, बल्कि उसे अनिवार्यता से मुक्त कर रही है। वे साफ कहती हैं—माँ बनना तभी अर्थपूर्ण है जब वह इच्छा से जन्म ले, भय या दबाव से नहीं। यह सोच स्त्री को पहली बार सम्पूर्ण मनुष्य के रूप में स्वीकार करती है, न कि केवल भविष्य की जननी के रूप में। जब चयन स्वतंत्र होगा, तभी मातृत्व भी सच्चे अर्थों में सम्मान का पात्र बनेगा।

'बेटियाँ जो माँ नहीं बनना चाहतीं' कोई क्षणिक फैशन नहीं, बल्कि चेतना की नई क्रांति है। यह बदलाव असहज है, क्योंकि यह उन गहरी और पक्की मान्यताओं को चुनौती देता है जिनमें समाज ने सदियों तक स्त्री को बाँध रखा था। इतिहास सिखाता है कि हर बड़ा परिवर्तन पहले बेचैनी और अव्यवस्था लाता है। आज की बेटियाँ केवल इतना पूछ रही हैं—क्या स्त्री का मूल्य उसकी कोख से तय होगा, या उसके विचार, उसकी चेतना और उसकी स्वतंत्रता से? इसका जवाब समय ही देगा। संभव है कि आने वाला समय अधिक ईमानदार, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक मानवतावादी हो—जहाँ मातृत्व सम्मानित विकल्प हो, आदेश या बाध्यता नहीं।

कृति आरके जैन
बड़वानी (मप्र)

आंचलिक

संत सिंगाजी परचरी पुराण कथा शुरू, निकली कलश यात्रा

दैनिक इंदौर संकेत

बांगरदा ● ग्राम में पांच दिवसीय संत सिंगाजी परचरी पुराण कथा के संगीतमय आयोजन का शुभारंभ गुरुवार से हुआ। कथा के मुख्य यजमान सरपंच रमेशचंद करोड़ा व उनकी पत्नी ने व्यासपीठ का पूजन कर कथावाचक मुकेश बाबा कालधा वाले का स्वागत किया। इससे पूर्व सुबह ग्राम के सिंगाजी मंदिर से पूरे गांव में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में सैकड़ों महिला-पुरुष श्रद्धालुओं के साथ ग्रामीण सामाजिक व राजनीतिक पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्य चौराहे पर कलश यात्रा का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। साथ ही परचरी पुराण कथा ग्रंथ का ग्रामीणों द्वारा विधिवत पूजन किया गया। कलश यात्रा के स्वागत में ग्रामीणों ने अपने-अपने घरों के सामने साफ-सफाई कर रंगोलियां सजाईं। शोभायात्रा में पूर्व सरपंच रमेश अरोड़ा अपने सिर पर संत सिंगाजी परचरी पुराण को धारण कर शामिल हुए। आयोजन के व्यवस्थापक राधेश्याम करोड़ा ने बताया कि संत सिंगाजी परचरी पुराण कथा का आयोजन 2 फरवरी तक किया जाएगा।

अवैध पटाखा फैक्ट्री केस- पिकअप ड्राइवर गिरफ्तार

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ● कलेक्ट्रेट बंगले के पीछे सिहाड़ा रोड स्थित सम्यक गोल्ड कॉलोनी में चल रही अवैध पटाखा फैक्ट्री के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मंगलवार को मौके से जब्त पिकअप के ड्राइवर अरबाज खान को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में ड्राइवर ने कांग्रेस नेता और प्रोफेसर इमरान परयानी का नाम कबूला है। पुलिस ने मौके से 2 हजार क्विंटल बारूद और विस्फोटक सामग्री जब्त की थी। फिलहाल मुख्य आरोपी इमरान परयानी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। गिरफ्तार पिकअप ड्राइवर अरबाज ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह इमरान परयानी के कहने पर पिकअप लेकर गया था। जब वह वहां पहुंचा, तो वहां 6-7 लोग मौजूद थे। ये लोग इमरान परयानी के साथ थे और व्यापारी व निवेशकर्ता बताए गए हैं। ड्राइवर ने कहा कि वह इनमें से सिर्फ इमरान परयानी को जानता है। मौके से परयानी की स्कूटी भी मिली थी। पुलिस का कहना है कि अब फरार आरोपी परयानी ही बताएगा कि बाकी के 6-7 लोग कौन हैं।

तहसीलदार बोले-आड़ी फसल फिर से खड़ी हो जाती है, कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने फटकारा तो सर्वे किया

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ●बारिश और तेज हवा के चलते फसलों को नुकसान पहुंचा है। खरीफ सीजन में सोयाबीन नुकसानी की मार झेल चुके किसानों के सामने यह दूसरी आफत थी। किसान अपने स्तर पर कोई आंदोलन करते, इससे पहले ही सरकार और विपक्ष अलर्ट हो गया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने किसानों के खेतों में जाकर हालात जाने, तो वहीं बजट सत्र के दौरान दिल्ली पहुंचे सांसद ने कहा कि, मैं दिल्ली में ही किसानों की बात रखूंगा। बुधवार को किल्लौद ब्लॉक में फसल नुकसानी के हालात देखने गए कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तमपालसिंह पुरनी को प्रशासनिक चुनौती का सामना करना पड़ गया। मौके पर आए तहसीलदार ने जिलाध्यक्ष और किसानों से कहा कि आड़ी फसल भी खड़ी हो जाती है। इसलिए थोड़ा इंतजार कर लेते है, फिर सर्वे कराएंगे। किल्लौद तहसीलदार

धनाजी गढ़वाल के इस तर्क पर उत्तमपालसिंह पुरनी ने आपत्ति ली और फटकार लगाई। तब तहसीलदार ने कहा कि, मैं भी 15 एकड़ का काश्तकार हूं। कई बार देखा है कि आड़ी फसल धूप और हवा से खड़ी हो जाती है। हम लोग सर्वे करवा रहे है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तमपालसिंह ने किल्लौद ब्लॉक के गड़बड़ी, हरिपुरा, सेमरूढ़, लछौड़ा, जूनापानी, खेड़ीपुरा, घाघरिया, मालुद, बड़गांव, कुंडिया, बिल्लोद, पाटाखाली, भुलवानी सहित कई गांवों का दौरा किया। खेतों में जाकर फसल नुकसानी के हालात देखें। उत्तमपालसिंह ने कहा कि किसानों की फसलों को बहुत नुकसान हुआ है। निर्वाचित जनप्रतिनिधि फोन पर अधिकारियों से बात करके इतिश्री ना करें। फील्ड पर आकर फसल नुकसानी का सर्वे कराएं और किसानों को उचित मुआवजा दिलाएं।

इधर, दिल्ली में गए सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने वहां से खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता को फोन किया। कहा कि किल्लौद और आसपास के इलाकों में मावठा गिरने से फसलों को नुकसान हुआ है। इसका सर्वे करवा लिजिए। कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि ठीक है, राजस्व विभाग के अधिकारियों को मौके पर भेजकर सर्वे करवा लेते है। सांसद पाटिल ने कहा कि आप सर्वे करवा लो, मैं दिल्ली में कृषि मंत्री शिवराजसिंह चौहान से मिलकर मुआवजे की बात रखूंगा। इस पर कलेक्टर ने कहा कि पहले सर्वे करवाते है कि नुकसान कितना हुआ है।

मतदाता सूची मामला- कांग्रेस ने कलेक्टर से की शिकायत

दैनिक इंदौर संकेत

बुरहानपुर ● कांग्रेस पार्षद दल ने बुधवार को कलेक्टर हर्ष सिंह से मुलाकात कर मतदाता सूची में दर्ज आपत्तियों का विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस का आरोप है कि ये आपत्तियां सोची-समझी राजनीतिक रणनीति के तहत लगाई जा रही हैं, जिसका उद्देश्य मतदाताओं के नाम सूची से हटाना है। कांग्रेस नेता अजय सिंह रघुवंशी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर को बताया कि आपत्ति दर्ज कराने वाले कई व्यक्तियों के नाम और पते तक मेल नहीं खा रहे हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया। प्रतिनिधिमंडल ने खानका वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि इस्हाक अली के नाम पर भी आपत्ति लगाए जाने का उदाहरण दिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिले भर में बड़े पैमाने पर ऐसी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। कांग्रेस ने कलेक्टर से इस मामले की गहन जांच कराने और शहर का माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इसी मुद्दे को लेकर नेपाननगर में भी दोपहर में एसडीएम को शिकायत कर जांच की मांग की गई।एक घटना में, कांग्रेस नेता अजय सिंह रघुवंशी ने एक शिकायतकर्ता को फोन किया, तो दूसरी ओर से 'रॉन्ग नंबर' कहकर आपत्ति लगाने की बात से इनकार कर दिया गया। ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, जहां आपत्तिकर्ता को भी पता नहीं है कि उसके नाम से शिकायत दर्ज की गई है।

खेत में मिली चीतल की लाश 4-5 साल का था नर हिरण

दैनिक इंदौर संकेत

बुरहानपुर ● पातोंडा गांव में गुरुवार को एक नर चीतल (हिरण) मृत अवस्था में मिला। ग्रामीणों की सूचना पर लालबाग वन चौकी की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। वन विभाग ने चीतल के शव को रेणुका स्थित वन विभाग डिपो पहुंचाया है, जहां उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। लालबाग वन चौकी प्रभारी योगेश सावकारे ने बताया कि पातोंडा ग्राम पंचायत से सूचना मिली थी कि कृषि क्षेत्र (खेत) में एक जानवर मृत पड़ा है। मौके पर पहुंचने पर टीम ने पाया कि मृत वन्यप्राणी एक नर चीतल था। उसकी उम्र लगभग चार से पांच साल बताई जा रही है।

जहरीला पदार्थ खाने से मौत की आशंका

चीतल की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। चौकी प्रभारी सावकारे के अनुसार, पोस्टमार्टम के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि उसकी मौत किसी जहरीली चीज के खाने से हुई है या इसके पीछे कोई अन्य कारण हैं। अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद निर्धारित एसओपी (मानक संचालन प्रक्रिया) के अनुसार चीतल का दाह संस्कार किया जाएगा।

वोटर लिस्ट से नाम काटने पर कांग्रेस का हंगामा, थाने में की शिकायत

दैनिक इंदौर संकेत

खंडवा ● वोटर लिस्ट से वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जाने के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने फॉर्म क्रमांक-7 के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए पहले मोघट थाना और फिर सिटी कोतवाली पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मौके पर पहुंचे एसडीएम ऋषि सिंघई ने आश्वासन दिया है कि मामलों का पंचनामा बनाया जाएगा और यदि आपत्तिकर्ता खुद उपस्थित नहीं होते हैं, तो आपत्तियां निरस्त कर दी जाएंगी। कांग्रेस का आरोप है कि सुनियोजित तरीके से फर्जी आपत्तियां लगाकर फॉर्म-7 का दुरुपयोग किया गया है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास हुआ है। पार्टी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि फर्जी आपत्तियां लगाने वालों पर निर्वाचन आयोग द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो पूरी एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया को निष्पक्ष नहीं माना जा सकता।

एसडीएम ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इधर, कांग्रेस ने निर्वाचन कार्यालय की पिछले 15 दिनों की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि इस पूरे मामले के पीछे कौन लोग शामिल हैं और आपत्तियां जमा करने कौन आया था। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने प्रशासन से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा, 'मुद्दा केवल आपत्तियां निरस्त करने का नहीं है, बल्कि यह जानना ज्यादा जरूरी है कि यह पूरा षड्यंत्र किसने और कैसे रचा। फॉर्म-7 कहां से और कैसे उपलब्ध कराए गए? फर्जी आपत्तियों वाले लिफाफे किसने प्रिंट कराए? इन्हें निर्वाचन कार्यालय में किसके माध्यम से जमा कराया गया? इन आपत्तियों का कोई आवक-जावक रजिस्टर में उल्लेख क्यों नहीं है? क्या निर्वाचन आयोग का डेटा आपत्तिकर्ताओं से साझा किया गया?'

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जानबूझकर बीएलओ और फील्ड अधिकारियों को मानसिक रूप से परेशान और हतोत्साहित किया जा रहा है। इसके बावजूद शासन-प्रशासन द्वारा दोषियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। शिकायत के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही हैं।

गंभीर को कोच पद से हटाने की कोई योजना नहीं : बीसीसीआई

मुंबई (एजेंसी) ● भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने टी20 सीरीज के बाद मुख्य कोच गौतम गंभीर को हटाये जाने की सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि देश में क्रिकेट को लेकर जिस प्रकार की दीवानगी रहती है। उसमें सभी अपने को विशेषज्ञ समझते हैं। साथ ही कहा कि सभी को अपनी राय देने का अधिकार है पर इस मामले में बोर्ड किसी भी प्रकार का फैसला अपने विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट के आधार पर लेता है। उन्होंने कहा, 'बीसीसीआई में एक क्रिकेट कमेटी है, जिसमें पूर्व क्रिकेटर शामिल रहते हैं। वे पूरी जिम्मेदारी के साथ सभी फैसले लेते हैं। वहीं टीम चयन के लिए हमारे पास पांच चयनकर्ता होते हैं, जो योग्यता के आधार पर इस पद तक पहुंचते हैं। ये ही लोग चयन से जुड़े फैसले लेते हैं। हर फैसले पर कोई न कोई अलग राय हो सकती है।' उन्होंने आगे कहा, 'हम इन सभी रायों को सुनते और समझते हैं पर अंतिम फैसला हमेशा क्रिकेट कमेटी और चयनकर्ता ही लेते है।' वहीं हाल में पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने कहा था कि अगर भारतीय टीम टी20 विश्वकप 2026 में असफल रहती है तो बीसीसीआई को कठिन फैसला लेते हुए गंभीर को कोच पद से हटा देना चाहिए।' गौरतलब है कि गंभीर की कोचिंग में भारतीय टीम टी20 क्रिकेट में ही अब तक सफल रही है। वहीं टेस्ट में उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा है और वह दो घरेलू सीरीज हारी है। इसके अलावा एकदिवसीय में भी टीम कुछ विशेष नहीं कर पायी है।

'कल्कि 2898 एडी-2' में दीपिका की जगह लेंगी साई पल्लवी

मुंबई (एजेंसी) ● नाग अश्विन की कल्कि 2898 एडी साल 2024 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म के पहले पार्ट में दीपिका पादुकोण नजर आई थीं। अब फिल्म को लेकर आए लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक, दीपिका पादुकोण की जगह साई पल्लवी ले सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कल्कि 2898 एडी-2 के प्रोड्यूसर्स फिल्म में साई पल्लवी को कास्ट करने का प्लान कर रहे हैं। फिल्म मेकर्स की तरफ से इस बात पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। रेडिट पर इस वायरल खबर पर सोशल मीडिया यूजर्स के भी रिएक्शन सामने आए हैं। एक यूजर ने पूछा, क्या 'रामायण पार्ट-2' की शूटिंग पूरी हो गई है? एक ने लिखा, साई पल्लवी की जगह सान्या मल्होत्रा को कास्ट करना चाहिए। एक ने लिखा, साई पल्लवी को 'कल्कि-2' में देखने के लिए उत्साहित हूं।

अभी संन्यास नहीं लेंगे केएल राहुल

नई दिल्ली (एजेंसी) ● बल्लेबाज केएल राहुल ने कहा है जब समय सही आयेगा वह खेल को अलविदा कहने में देर नहीं करेंगे। 33 साल के राहुल ने कहा कि अभी वह समय नहीं आया है और जब आयेगा तो वह फैसला लेने में देर नहीं करेंगे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन के साथ बातचीत में राहुल ने कहा कि खेल के अलावा भी जीवन में काफी कुछ है। इसलिए संन्यास का फैसला लेना उनके लिए कठिन नहीं रहेगा। राहुल ने पीटरसन से कहा, 'मैंने एक समय संन्यास के बारे में भी सौचा था पर मुझे नहीं लगता कि इसका फैसला कठिन होगा। साथ ही कहा कि अगर आप अपने प्रति ईमानदार हैं तो जब समय आएगा तब इसे नहीं टालेंगे।' राहुल ने कहा कि वह अपने को एक बड़ा स्टार या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं मानते हैं, जिसके कारण उनके लिए भविष्य में संन्यास का फैसला आसान रहेगा। उन्होंने कहा, ' वह शांति से संन्यास लेकर जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। उनका मानना है कि परिवार भी साथ है, इसलिए बस वही करो जो अच्छा लगता हो।'राहुल ने कहा, 'हमारे देश और दुनिया भर में क्रिकेट चलता रहेगा पर जीवन में इससे आगे भी काफी कुछ है। मुझे लगता है कि मेरी ये सोच हमेशा से रही है पर जब से मैं पिता बना हूं तब से जीवन के प्रति मेरा नजरिया पूरी तरह से ही बदल गया है। यही मेरी सोच है।' वह अपनी फिटनेस को लेकर भी संघर्ष करते रहे हैं। जिसके कारण उनके खेल में निरंतरता की कमी रही है।

टी20 विश्व कप: भारत खिताब का सबसे बड़ा दावेदार - रवि शास्त्री

नई दिल्ली (एजेंसी) ● टी20 विश्व कप 2026 के लिए भारतीय टीम के पूर्व मुख्य कोच रवि शास्त्री का मानना है कि मौजूदा चैंपियन भारत इस बार इतिहास रच सकता है और लगातार दो बार ख़िताब जीतने वाली पहली टीम बन सकता है। भारतीय टीम का मौजूदा प्रदर्शन बेहद ज़बरदस्त रहा है। 2024 में टी 20 विश्व कप का ख़िताब जीतने के बाद से टीम इंडिया ने कोई भी द्विपक्षीय सीरीज या टूर्नामेंट नहीं गंवाया है। आंकड़ों पर नज़र डालें तो भारत का जीत-हार का रिकॉर्ड 32-5 का है, जो किसी भी विरोधी टीम के लिए खतरे की घंटी है। टी 20 रैंकिंग में नंबर 1 पर काबिज़ भारतीय टीम के पास इस वक्त दुनिया का सबसे बेहतरीन दल है। टीम में नंबर 1 टी 20 बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा और नंबर 1 टी 20 गेंदबाज़ वरुण चक्रवर्ती शामिल हैं, जो विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं। शास्त्री ने टीम की मजबूती पर बात करते हुए कहा, 'मुझे लगता है कि डिफेंडिंग चैंपियंस स्पष्ट रूप से जीत के प्रबल दावेदार के तौर पर शुरुआत करेंगे। अगर आप एक-एक खिलाड़ी को देखें, उनकी मौजूदा फ़ॉर्म, मैच फ़िटनेस और हाल के दिनों में उन्होंने जितना क्रिकेट खेला है, यह सब उन्हें साफ़ तौर पर फेवरेट बनाता है। ख़ास तौर पर जब आप उनके टॉप ऑर्डर और उनकी मौजूदा फ़ॉर्म को देखते हैं, तो स्थिति और भी मजबूत नजर आती है।'

फिल्मों में श्रिया सरन के 25 साल पूरे, साझा किए अनुभव

मुंबई (एजेंसी) ●अभिनेत्री श्रिया सरन ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। अभिनेत्री ने इतने लंबे करियर में इंडस्ट्री में आए कई बड़े बदलावों को महसूस किया है। श्रिया सरन ने इस मौके पर अपने सफर, तकनीकी बदलावों और आज के दौर की चुनौतियों पर खुलकर बात की। श्रिया ने बताया कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब फिल्म सेट्स का माहौल आज से बिल्कुल अलग था। उस समय इस्तेमाल होने वाली लाइट्स बेहद तेज होती थीं, जो आंखों को चुभती थीं और कई बार कलाकारों के लिए असहज स्थिति पैदा कर देती थीं। कैमरे भारी हुआ करते थे और तकनीक भी सीमित थी। शूटिंग के दौरान कलाकारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था और कैमरे की आवाज सुनकर ही यह अंदाजा लगता था कि सीन शुरू हो चुका है। उस दौर में काम करना ज्यादा मेहनत और धैर्य की मांग करता था। उन्होंने कहा कि आज तकनीक ने फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया है। अब सॉफ्ट लाइट्स का इस्तेमाल होता है, जिससे आंखों पर दबाव नहीं पड़ता।

कैमरे पहले से कहीं ज्यादा हल्के और एडवांस हो गए हैं, जिससे शूटिंग न सिर्फ आसान बल्कि तेज भी हो गई है। इन बदलावों का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि कलाकार अब तकनीकी परेशानियों से हटकर अपने अभिनय पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और काम का माहौल भी पहले से ज्यादा आरामदायक हो गया है। श्रिया सरन ने इंडस्ट्री के वर्किंग सिस्टम में आए बदलावों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पहले कलाकारों को केवल एक मैनेजर के जरिए काम संभालना पड़ता था, लेकिन अब एजेंसियों का दौर है। आज कलाकारों को कई लोगों से तालमेल बैठाना पड़ता है।

उज्जैन संभाग

गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन 7 फरवरी से

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ●रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए किसान पंजीयन 7 फरवरी से 7 मार्च तक करवा सकेंगे। पंजीयन की नि:शुल्क व सशुल्क व्यवस्था निर्धारित केंद्रों पर की जा रही है। इस वर्ष गेहूं का एमएसपी 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।

भूमि आवंटन में आपत्ति के लिए 30 दिन का समय तय

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ●ग्राम दाउदखेड़ी स्थित भूमि सर्वे क्र. 63/3 रकबा 18.2010 हेक्टेयर में से 0.80 हेक्टेयर भूमि पर आवासीय ट्रेनिंग सेंटर निर्माण के लिए भूमि आवंटन किया जाना है। जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा भूमि आवंटन का आवेदन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ग्रामीण में प्रस्तुत किया है। यदि किसी को आपत्ति हो तो अनु. अधिकारी राजस्?व ग्रामीण कार्यालय में 30 दिन में दे सकते हैं।

आरटीओ के विरोध में बस खड़ी की, स्लीपर कोच पर रोक लगाए जाने से नाराज ऑपरेटर

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● आरटीओ द्वारा स्लीपर कोच बसों पर अचानक रोक लगाए जाने से आक्रोशित टूरिस्ट बस आपरेटरो ने गुरुवार को विरोध स्वरूप 100 से अधिक बसें सामाजिक न्याय परिसर में खड़ी कर दी। टूरिस्ट बस आपरेटर एसोसिएशन ने कहा कि स्लीपर कोच बसों पर रोक लगाते हुए बसों को आरटीओ द्वारा बंद कर दिया गया। जिसके कारण गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। इस निर्णय से केवल बस मालिक ही नहीं, बल्कि टूरिस्ट एजेंट, गाइड, ड्राइवर व स्टाफ, धर्म यात्रा से जुड़े छोटे व्यवसाय सहित कई अन्य लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। जिसके चलते बसों को अस्थाई रूप से रोक दिया गया है।

टूरिस्ट बस ऑपरेटरों ने कहा ये सभी बसें उज्जैन में ही आरटीओ द्वारा विधिवत पास की गई थीं। ऐसे में इन्हें बिना पूर्व सूचना या समय दिए एकदम से बंद कर देना व्यवसायिक रूप से भी और नैतिक रूप से भी उचित नहीं है। इस निर्णय से केवल बस मालिक ही नहीं, बल्कि टूरिस्ट एजेंट, गाइड, ड्राइवर व स्टाफ, धर्म यात्रा से जुड़े छोटे व्यवसाय सहित कई अन्य लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। हजारों परिवारों की आजीविका इस कार्य पर निर्भर है। साथ ही, इससे धार्मिक यात्राओं की व्यवस्था पर भी सीधा प्रभाव पड़ रहा है।

टूरिस्ट बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने सभी संबंधित विभागों से निवेदन किया हैं कि इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए और उचित समाधान निकाला जाए, ताकि रोजगार और धार्मिक यात्राओं दोनों की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। इस निर्णय की वजह से धार्मिक यात्राएं और बारातों का आवागमन काफी प्रभावित हो गया है।

एसोसिएशन के सदस्य भावन कालरा ने बताया कि ऋ्रह ने जिन बसों को 2019 में 2ङ्ग2 सीट का फिजिकल चेक कर फिटनेस पास किया उसका रजिस्ट्रेशन किया गया। 6 साल तक बस चलती रहीं 28 दिसम्बर 2025 तक ऐसे सभी बसों का रजिस्ट्रेशन किया गया। अब कुछ बसों में हुई घटना को लेकर एकाएक ऋ्रह ने रोक लगाकर कहा कि सभी बसों को 2 ङ्ग 1 करना होगा।

उज्जैन में कुल 839 ऐसी बसें है जिनको आरटीओ ने ब्लॉक कर दिया। अगर आरटीओ के नियम से बसों को मोडिफाइड करवाया गया तो कम से कम 7 से 10 लाख रुपए खर्चा आएगा। फिलहाल उज्जैन की 100 बसों को खड़ा कर दिया गया। इस दौरान सभी बसों में करीब 1 साल का समय लग जायेगा। प्रदेश में करीब ऐसी 8 हजार बसें है।

17 वर्षीय जिम्नास्ट की 14 दिन बाद मौत, वार्मअप करते समय सिर के बल गिरा था

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● मध्यप्रदेश टीम की ओर से कोलकाता गए उज्जैन के 17 वर्षीय जिम्नास्ट उजैर अली की इलाज के दौरान मौत हो गई। जिम्नास्टिक नेशनल चैंपियनशिप से पहले 16 जनवरी को वार्मअप के दौरान गिरने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 14 दिन तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 28 जनवरी को उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजन का आरोप है कि कोच और मैनेजर उसे अस्पताल में छोड़कर लौट गए थे। परिवार ने बताया कि उजैर का शव फ्लाइट से इंदौर लाया जा रहा है, जहां से उसे उज्जैन पहुंचाया जाएगा। इसके बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (स्लस्क्लइ) की ओर से कोलकाता में आयोजित नेशनल चैंपियनशिप के लिए उजैर अली 12 जनवरी को टीम के साथ रवाना हुए थे। 16 जनवरी को प्रतियोगिता शुरू होने से पहले दोपहर करीब 1:50 बजे वह बीएनआर सेंटर में अभ्यास कर रहे थे। इसी

दौरान हाथ फिसलने से वह सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। हादसे में उन्हें गर्दन में गंभीर चोट आई, जिसके बाद उन्हें तत्काल कोलकाता के पीजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 14 दिन तक चले इलाज के दौरान उजैर की हालत गंभीर बनी रही। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद कोच और मैनेजर उन्हें अस्पताल में छोड़कर लौट गए। उजैर के मामा डॉ. साकिब ने बताया कि जब परिवार के सदस्य कोलकाता पहुंचे, तब तक टीम के कोच और मैनेजर अस्पताल में मौजूद नहीं थे। उजैर की मौत के बाद उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन नहीं उठाया गया। उज्जैन की जामा मस्जिद क्षेत्र में रहने वाले मजहर अली के बेटे उजैर अली अंडर-17 जिम्नास्टिक टीम के सदस्य थे। वे बचपन से पढ़ाई के साथ जिम्नास्टिक्स का अभ्यास कर रहे थे। जिला और राज्य स्तर पर कई पदक जीत चुके उजैर को मध्यप्रदेश के टॉपर जिम्नास्ट का खिताब भी मिला था। नेशनल लेवल पर भी उनका चयन हुआ था। कोलकाता जाने वाली टीम के मैनेजर रामसिंह बनिहार ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि हम लोग 12 जनवरी को टीम अंडर-17, 19 टीम के 43 बच्चों को लेकर कोलकाता पहुंचे थे। वहां 15,16 और 17 जनवरी को तीन दिन प्रतियोगिता थी। 16 जनवरी को बीएनआर सेंटर में जिम्नास्टिक की प्रतियोगिता 2 बजे से थी। उससे 10 मिनट पहले उजैर वार्मअप कर रहे थे, इस दौरान वे सिर के बल गिर गए और घायल हो गए।

शहर में हो सकेगी आईएएस स्तर के अफसरों की भी ट्रेनिंग

दैनिक इंदौर संकेत

उज्जैन ● प्रदेश में उज्जैन और ग्वालियर में एक डिजाइन में राजस्व का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान बनने जा रहा है। शासन ने दोनों ही स्थानों के लिए एक आर्किटेक्ट नियुक्त किया, जो कि डिजाइन फाइनल करने में जुटा है। उज्जैन में न केवल पटवारियों की बल्कि राजस्व विभाग से जुड़े सभी अधिकारियों की ट्रेनिंग हो सकेगी। जिला प्रशासन में नजूल के अधिकारी आलोक चौरे ने बताया कि शासन ने लालपुर के पटवारी स्कूल को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान के रूप में डेवलप करने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में ग्वालियर के आला अधिकारियों की टीम हाल ही में उज्जैन आकर निरीक्षण करके गई हैं।

तय हुआ है कि दोनों ही शहरों में एक ही डिजाइन का प्रशिक्षण संस्थान बनेगा। जल्द डिजाइन फाइनल होकर आएगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लालपुर के पटवारी स्कूल के पास वर्तमान में 8 बीघा जमीन में से 2 बीघा पर निर्माण है। विस्तार के लिए 4 बीघा अतिरिक्त चाहिए, ताकि परिसर 12 बीघा होकर निर्माण हो सके।

बीआरटीएस पर एलिवेटेड कॉरिडोर की तैयारी, उधर लग गई याचिका

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● एमपी हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में बीआरटीएस रेलिंग नहीं हटाने को लेकर शासन, प्रशासन घिरा हुआ है। इसमें काम में देरी के लिए वजह पीडब्ल्यूडी ने प्रस्तावित 6.1 किमी लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बताया है। इसी को लेकर गुरुवार, 29 जनवरी को जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बड़ी बैठक भी हो रही है। इसी को लेकर एक याचिका भी हाईकोर्ट में दायर हो गई है। साथ ही, मामला फंस गया है। यह याचिका अतुल सेठ ने लगाई है। इसमें सवाल उठा गया है कि इस कॉरिडोर को लेकर दो सर्वे पहले हुए थे। इस सर्वे में इस कॉरिडोर की यूटिलिटी ही साबित नहीं हुई है। एक सर्वे में 15 फीसदी की उपयोगी पाया गया, तो दूसरे सर्वे में भी संतोषजनक स्थिति नहीं थी। ऐसे में इस मामले में 350 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या तुक है। वहीं इसके निर्माण के चलते इंदौर की सबसे व्यस्त एबी रोड पर कम से कम दो साल तक जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा।

अतुल सेठ ने सवाल उठाए हैं कि सरकार के पीएस नीरज मंडलोई ने ही साल 2022–23 में इसे निरस्त करने की अनुशंसा की थी। इस दौरान ठेकदार कंपनी के 30 करोड़ रुपए मुआवजे पर कानूनी सलाह की बात भी उठी थी। वहीं इसमें कराए गए सर्वे जो एक निजी कॉलेज से हुआ था केवल 15 फीसदी उपयोगी पाया गया था। तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने दूसरा सर्वे कराया, इसमें भी खास उपयोगी नहीं पाया गया है। यह बात भी याचिका में उठाई गई है कि कई सर्वे में यह पाया गया कि लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाना बेहतर नहीं है। इसकी जगह अलग–अलग चौराहों पर फ्लाईओवर बनाना अधिक उपयोगी है। एलआईजी से नवलखा तक हर थोड़ी दूर में एक चौराहा है। इसमें ट्रैफिक बंट जाता है। एलआईजी से नवलखा तक सीधे जाने वाले वाहन चालक बहुत कम संख्या में हैं। अधिकांश ट्रैफिक इंडस्ट्री हाउस तिराहा, पलासिया, गीताभवन, शिवाजी वाटिका चौराहे पर ही कट जाता है। यह कॉरिडोर साल 2019 से कांग्रेस सरकार के समय से चल रहा है। तब इसे मंजूर किया गया था। बाद में बीजेपी सरकार आने पर इसकी डिजाइन व अन्य मुद्दे को लेकर मामला उलझा रहा। वहीं, मोहन सरकार के समय फिर इस पर काम की बात हुई। अब जब हाईकोर्ट में केस हुआ तो इस कॉरिडोर का मुद्दा फिर सुर्खियों में आ गया। वहीं चिंता आमजन की है। दरअसल इसके पैरेलल दो और रोड है। एबी रोड पर काम चलने के बाद ट्रैफिक रिंग रोड पर शिफ्ट होगा। यहां पहले ही मेट्रो का और ब्रिज का काम चल रहा है। इससे ट्रैफिक की हालत बेहाल है। वहीं फिर बायपास की ओर जाओ तो यहां भी फ्लाईओवर के काम के चलते लंबे जाम आते हैं, छोटे बोगदे से वाहन फंसते हैं। फिर शहर में आने–जाने के लिए भी यह दूर पड़ता है। ऐसे में इस कॉरिडोर को लेकर वैसे ही चिंता है। यह प्रोजेक्ट 350 करोड़ का है। इसमें तीन अहम चौराहों शिवाजी प्रतिमा, गीताभवन व पलासिया पर भुजाएं प्रस्तवित की गई है। इससे वाहन चालक डायवर्ट हो सकें। ब्रिज पर रोटरी भी प्रस्तावित है। दिसंबर में सीएम ने इसकी घोषणा की थी। गुजरात की कंपनी को इसका ठेका दिया गया है। हाईकोर्ट में अधिकारी इस पर फरवरी में काम शुरू होने की बात कह चुके हैं।

रेलिंग मामले से बचने के लिए उठा कॉरिडोर मुद्दा

बीआरटीएस की रेलिंग हटाने में देरी को लेकर अधिकारी लगातार हाईकोर्ट की फटकार झेल रहे हैं। अधिकारियों ने इस देरी की वजह कॉरिडोर को बताया है। कहा गया कि इसे सीएम दिसंबर में मंजूर कर चुके हैं। काम का भूमिपूजन भी हो चुका है और फरवरी से इसका काम शुरू कर रहे हैं। इसलिए पूरे कॉरिडोर में इस हिस्से को छोड़कर बाकी बचे 3.1 किमी हिस्से में हम रैलिंग हटा देते हैं।

हाईकोर्ट में पेश बीआरटीएस रेलिंग हटाने के टेंडर में भी चूक, निगमायुक्त को बोलना पड़ा सॉरी–सॉरी

ट्रैफिक केस पर इंदौर हाईकोर्ट खंडपीठ की नजर है। साथ ही, अधिकारियों की लगातार पेशी चल रही है। वहीं, इसमें भी नगर निगम की चूक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बीआरटीएस रेलिंग हटाने के टेंडर में रेलिंग हटाने की बात ही नहीं लिखी है। इस मामले में जब हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने सख्ती दिखाई तो निगमायुक्त क्षितिज सिंघल सॉरी–सॉरी बोलते नजर आए। अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। वहीं हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि हमें काम चाहिए, बहाने नहीं। बीती सुनवाई में निगम ने बताया था कि रेलिंग हटाने का टेंडर लेने वाला ठेकेदार काम नहीं कर रहा है। वह ठेकेदार काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम एक छोटा टेंडर 15 दिन की प्रक्रिया का जारी कर रहे हैं। इसे फाइनल होने में सात दिन लगेंगे। इस टेंडर को वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बागड़िया ने पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ बीआरटीएस का स्क्रैप और बिल्डिंग मटेरियल हटाने का जिक्र है। इसमें रेलिंग हटाने की बात नहीं है। यह निगम का खेल है। इस पर निगमायुक्त (आईएएस क्षितिज सिंघल) असहज हुए और सॉरी–सॉरी कहने लगे। उन्होंने फिर अधिकारियों से जानकारी ली। साथ ही, मोबाइल में कोर्ट को टेंडर की अंग्रेजी कॉपी दिखाई। उन्होंने कहा कि रेलिंग हटाने का काम इसमें शामिल है। इस पर बागड़िया ने कहा कि जिस मामले में कोर्ट गंभीर है, इसमें निगम इस तरह की लापरवाही कर रहा है। कोर्ट ने इस पर खासी आपत्ति ली है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता ने एक और बात पर आपत्ति ली है। उन्होंने कहा कि जिस काम के लिए हाईकोर्ट से मंजूरी है, उसमें फिर से टेंडर प्रक्रिया में ही 22 दिन ले रहे हैं। जनता को लगातार परेशानी हो रही है। निगम खुद क्यों यह काम नहीं कर सकता है। टेंडर में फिर ठेकेदार नहीं आया तो क्या होगा।

इस पर हाईकोर्ट बेंच ने फिर कहा कि इस काम में इतनी हिचकिचाहट क्यों कर रहे हैं? यह तो खुद सरकार का फैसला है। भोपाल में तो तत्काल हट गया था। इस पर निगमायुक्त ने कहा कि रेलिंग हटा सकते हैं, लेकिन बस स्टॉप हटाने के संसाधन उनके पास नहीं हैं। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी ने एलिवेटेड कॉरिडोर के कार्य पर चर्चा की, जो शुरू होने वाला है। अधिकारी ने कहा कि कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) फरवरी में एलिवेटेड कॉरिडोर का काम शुरू करेगा। वहीं इंदौर बीआरटीएस के बाकी 3.1 किमी में रेलिंग हटाने और सेंट्रल डिवाइडर बनाने का काम होना है। बताया गया कि इस काम को पूरा करने में तीन महीने लगेंगे। बेंच ने अधूरे डिवाइडर और बीआरटीएस काम के कारण यातायात समस्याओं पर चिंता जताई है। साथ ही पूछा कि क्या अधूरे टेंडर को देखते हुए काम के लिए एक सरकारी एजेंसी नियुक्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि वह टेंडर प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के बारे में चिंतित नहीं हैं, बल्कि कार्य को पूरा करने के बारे में अधिक चिंतित हैं। निगम अभी तक बीआरटीएस मामले में चार बार टेंडर निकाल चुका है। इस बार काम की लागत 1.5 करोड़ रखी जाएगी। पहले यह 3.50 करोड़ का निकाला गया था। एक साइड की रेलिंग निकाली जा चुकी है। अभी दूसरी साइड की रेलिंग और 18 बस स्टैंड को हटाना बाकी हैं।

ईडी का 20.47 करोड़ के गबन के आरोपी अलीराजपुर के बीईओ के खिलाफ चालान

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● श्रष्ठ ने अलीराजपुर के बीईओ कमल राठौर पर 20.47 करोड़ के गबन का चालान पेश किया। राठौर और अन्य ने फर्जी बिलों से वेतन, पेंशन और छात्रवृत्तियों का गबन किया। राठौर ने अकेले 14.5 करोड़ रुपए हड़प लिए, 57 बैंक खातों के जरिए राशि शिफ्ट की। जांच में 134 बैंक खातों में राशि शिफ्ट करने का खुलासा हुआ, आरोपियों ने राशि निकाली। श्रष्ठ ने राठौर की संपत्तियां अटैच की, 4.30 करोड़ रुपए की संपत्ति और 25 लाख नकद जब्त किए।

अलीराजपुर के कट्ठीवाड़ा में बीईओ कमल राठौर व अन्य द्वारा किए गए 20.47 करोड़ के गबन में प्रवर्तन निदेशालय (श्रष्ठ) ने स्पेशल कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। इस मामले में राठौर को अगस्त 2025 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के पास दर्ज स्नद्बक्र के आधार पर इसमें राठौर सहित कुल पांच आरोपियों पर मनी लाण्ड्रिंग का केस हुआ था।

आरोप है कि इनके द्वारा अप्रैल 2018 से जुलाई 2023 के बीच क्ष्श्वह्र ऑफिस से 20.47 करोड़ रुपए के संदिग्ध और फर्जी भुगतान किए। इसके लिए वेतन, त्नड्डस्, पेंशन और छात्रवृत्ति जैसे कई मदों में फर्जी बिल लगाए गए थे। बाद में यह राशि अलग–अलग निजी बैंक खातों में शिफ्ट कर निकाली गई। इसमें 35 खाते तो राठौर सरनेम वाले रिश्तेदारों के थे। इस मामले में तत्कालीन 3 खंड शिक्षा अधिकारी, 2 लेखापाल और 1 प्रधानाध्यापक सहित कुल 6 लोगों पर स्नद्बक्र दर्ज हुई है। साल अगस्त 2023 में कोष एवं लेखा विभाग की जांच के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था। मुख्य आरोपी कमल राठौर था जिसे अगस्त 2025 में गिरफ्तार किया गया।

ईडी अटैच कर चुका 4.30 करोड़ की संपत्ति

ईडी ने उसकी संपत्तियों की जांच के लिए छापे भी मारे थे। इसमें कई संपत्तियों की जानकारी मिली थी जो अलीराजपुर से लेकर इंदौर तक थी। इसमें 14 अचल संपत्तियों को अटैच किया गया जिसकी कीमत 4.30 करोड़ रुपए थी। वहीं 25 लाख नकद भी जब्त किए गए थे।

राठौर ने अकेले 14 करोड़ रखे

श्रष्ठ की जांच में खुलासा हुआ कि कमल राठौर ने अकेले करीब 14.5 करोड़ रुपए हड़प लिए। यह पैसा 57 बैंक खातों के जरिए घुमाया गया। कुल 134 से ज्यादा खातों में राशि शिफ्ट कर निकाली गई। साल 2018–19 से 2023–24 के बीच खंड शिक्षा कार्यालय कट्ठीवाड़ा में यह पूरा गबन किया गया।

एक्रोपोलिस प्रबंधन को एबीवीपी ने दी चेतावनी

करोड़ों के हेरफेर व अवैध फीस वसूली पर जल्द ही फैसला लें...

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● अभाविप इंदौर द्वारा एक्रोपोलिस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंदौर में लंबे समय से चल रहे करोड़ों रुपये के फीस घोटाले को कल विद्यार्थियों के साथ आंदोलन के माध्यम से उजागर किया गया। यह आंदोलन विद्यार्थियों से की जा रही अनधिकृत, मनमानी एवं नियम विरुद्ध फीस वसूली के विरोध में किया गया। गुरुवार को मीडिया से चर्चा में अभाविप इंदौर महानगर ने इस पूरे मामले को तथ्यों एवं दस्तावेज़ों आधार के साथ मीडिया के समक्ष प्रस्तुत किया। परिषद ने बताया कि एक्रोपोलिस महा विद्यालय द्वारा एडमिशन एंड फीस रेगुलेटरी कमेटी (एएफआरसी) के नियमों का उल्लंघन करते हुए विद्यार्थियों से डेवलपमेंट फीस, मिसलेनियस फीस एवं अन्य शुल्कों के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक राशि वसूली जा रही है।

व्यवस्थित शोषण-चर्चा में यह भी स्पष्ट किया गया कि यह केवल एक सत्र या कुछ विद्यार्थियों तक सीमित विषय नहीं, बल्कि वर्षों से संचालित व्यवस्थित आर्थिक शोषण है, जिससे हजारों विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं और जिसकी कुल राशि करोड़ों रुपये तक पहुंचती है। अभाविप ने इसे शिक्षा के नाम पर की जा रही धोखाधड़ी करार दिया। विद्यार्थी परिषद ने मांग की कि विद्यार्थियों से ली गई अवैध फीस तत्काल वापस की जाए, भविष्य की फीस को एएफआरसी के नियमानुसार निर्धारित किया जाए, तथा इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। अभाविप के महानगर मंत्री देवेश गुर्जर ने स्पष्ट किया कि यदि एक्रोपोलिस महाविद्यालय प्रशासन शीघ्र कोई ठोस निर्णय नहीं लेता, तो यह आंदोलन और अधिक व्यापक रूप लेगा। जब तक विद्यार्थियों को पूर्ण न्याय नहीं मिलता अभाविप का संघर्ष अडिग एवं निरंतर रहेगा।

अल्पसंख्यक इलाकों में मतदाताओं के खिलाफ लगाई आपत्ति

बड़ी है गडबड़: फर्जी आपत्ति से मतदाता कम बीएलओ ज्यादा हो रहे परेशान, किया विरोध

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर मतदाताओं से ज्यादा अब बीएलओ परेशान होने लगे हैं। हालत यह हो गई है कि बीएलओ खुलकर विरोध में उतर आए हैं। वहीं दूसरी ओर शहर के मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में थोकबंद फार्म 7 भरकर जमा किए गए हैं। इसमें एक-एक नाम से 50 से 60 फार्म 7 भरे गए हैं। सभी फार्म-7 का फार्मेट प्रिंट किया हुआ है, केवल आपत्ति लगाने वाले का नाम, एपिक नंबर और साइन ही पेन से लिखी हुई है। मतलब चुनाव आयोग ने जो मतदाताओं की सूची जारी की, उस सूची को सामने रखकर करीब हर घर से दो से तीन लोगों के खिलाफ आपत्ति लगाई गई है। इन आपत्तियों के कारण मतदाता तो कम, इन क्षेत्रों के बीएलओ ज्यादा परेशान हो रहे हैं।

शहर के खजराना, चंदन नगर, आजाद नगर के साथ ही अन्य इलाकों में थोकबंद फार्म 7 भरकर आपत्ति ली है कि मतदाता ने इस क्षेत्र को स्थाई रूप से छोड़ दिया है। यानि वो इस क्षेत्र में नहीं रहता है। इसमें मतदाता का नाम और इपिक नंबर आदि प्रिंट किया हुआ है और एक नाम से कई मतदाताओं के खिलाफ एक जैसी आपत्ति लगाई गई है। जिस नाम से जैसे पीयूष मिश्री, दिनेश जोशी आदि आपत्ति लगाई गई है, वो आस-पास तो क्या दूर-दूर तक नहीं रहते हैं, ऐसे में उन्हें कैसे जानकारी मिली कि फलां व्यक्ति उक्त पते पर नहीं रह रहा है। खजराना में तो वार्ड 39 के पार्षद पति के नाम पर ही आपत्ति लगा दी। हर कालोनी में 250 से 300 तक आपत्ति लगाते हुए फार्म 7 दाखिल किए गए हैं, जो सिरे से फर्जी लग रहे हैं, इसके बाद भी इन्हें स्वीकार कर लिया गया है, जो बीएलओ के लिए सिरदर्द बन गया है।

एमजीएम मेडिकल कॉलेज में शुरू होगी लेप्रोस्कोपी ट्रेनिंग

अब नहीं जाना होगा विदेश, सर्जरी और स्त्री एवं प्रसूति रोग में होगी ट्रेनिंग

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर ● चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कॉलेज के सर्जरी और स्त्री रोग विभाग में जल्द ही लेप्रोस्कोपी (दूरबीन के जरिए सर्जरी) की एडवांस ट्रेनिंग शुरू होने जा रही है। इस पहल के बाद अब स्थानीय डॉक्टरों को विशेष ट्रेनिंग के लिए बड़े महानगरों या विदेशों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, यह ट्रेनिंग प्रोग्राम न केवल एमजीएम के आंतरिक डॉक्टरों के लिए होगा, बल्कि बाहरी प्रत्याशी भी इसमें भाग ले सकेंगे। ट्रेनिंग की अवधि 7 दिवसीय / 14 दिवसीय या एक माह होगी इस ट्रेनिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रशिक्षण देने वाले विशेषज्ञ स्वयं एमजीएम मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ और अनुभवी डॉक्टर होंगे। प्रतिभागियों को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से लेप्रोस्कोपी की बारीकियां सिखाई जाएंगी, जिससे वे जटिल ऑपरेशन को आसानी से करने में सक्षम हो सकेंगे। डॉ अरविंद घनघोरिया, डीन एमजीएम मेडिकल कॉलेज ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर में ही विश्वस्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना हमारा उद्देश्य है इससे न केवल डॉक्टरों का कौशल बढ़ेगा बल्कि मरीजों को भी बेहतर इलाज मिलेगा। बाहर जाने की जरूरत होगी खत्म अब तक कई डॉक्टरों को लेप्रोस्कोपी की एडवांस ट्रेनिंग के लिए दिल्ली, मुंबई या विदेशों में जाना पड़ता था, जो काफी खर्चीला और समय लेने वाला होता था। एमजीएम में यह सुविधा शुरू होने से इंदौर अब चिकित्सा शिक्षा के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरेगा।

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 19 मार्च को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली (एजेंसी) ● सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि इन नियमों की भाषा में साफ-सफाई नहीं है। इसलिए इनकी जांच जरूरी है, ताकि नियमों की भाषा ठीक की जा सके और उनका दुरुपयोग न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इन नियमों को फिर से बनाने को कहा है और तब तक इन पर रोक लगी रहेगी। इसके अलावा, कोर्ट ने केंद्र से जवाब भी तलब किया है। इसे लेकर एक कमेटी भी गठित करने को कहा गया है। साथ ही, कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल 2012 में नोटिफाई किए गए तष्ट रेगुलेशन ही लागू रहेंगे। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई में हो रही है। इस दौरान कोर्ट ने कई तीखे सवाल भी पूछे हैं। सीजेआई ने सवाल किया कि आजादी के 75 साल बाद भी हम जातियों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। क्या यह नया कानून हमें पीछे ले जाएगा? वहीं, जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने अमेरिका की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है हम उस स्थिति तक नहीं पहुंचेंगे, जहां कभी अश्वेत और श्वेत बच्चों को अलग-अलग स्कूलों में पढ़ाया जाता था।

सीजेआई सूर्यकांत ने एसजी तुषार मेहता से कहा कि एक कमेटी बनाने पर विचार किया जाए। कमेटी में कुछ प्रतिष्ठित लोग हो सकते हैं। यह कमेटी इस मुद्दे की समीक्षा करेगी। ताकि समाज बिना किसी विभाजन के आगे बढ़ सकेगा। साथ ही, सभी मिलकर विकास कर सकेंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 15 जनवरी 2026 से देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026 लागू कर दिए हैं। इस नियम का मकसद कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना और सभी वर्गों के लिए समान, सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना बताया गया है। (UGC Regulations 2026 का राजपत्र देखिए)

जयपुर में करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर सवर्ण समाज समन्वय समिति (स–4) का गठन किया है, ताकि रेगुलेशन के खिलाफ संगठित विरोध किया जा सके। दुविधा यह है कि अब तक सरकार की ओर से कोई बड़ा नेता इस मसले पर बोलने को तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और जिस तष्ट ने इस नियम को लागू किया है, उसके चेयरमैन विनीत जोशी हैं।

सख्त कार्रवाई का डर

जीसी ने नए नियमों का पालन नहीं करने वाले कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कड़ी चेतावनी दी है। अगर कोई संस्थान इन नियमों का पालन नहीं करता, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें तष्ट की योजनाओं से बाहर करना, कोर्स बंद करना, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर रोक लगाना, और संस्थान की मान्यता रद्द करना शामिल है। इन नियमों में OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) की जातियों से आने वाले छात्रों को भी शामिल किया गया है। जनरल कैटेगरी से आने छात्रों के साथ भेदभाव बताया जा रहा है। विरोध करने वालों का मानना है कि इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है। सिर्फ जनरल कैटेगरी भर के होने से ही वो दोषी हो जाएंगे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक : अक्षय तिवारी द्वारा मेसर्स डी.बी. कार्प लिमि. 44-45/ए, 50-51/ए, सेक्टर एफ इंडस्ट्रीयल एरिया, सांवेर रोड, इंदौर (म.प्र.) - 452008 से मुद्रित एवं 5/6, नार्थ राजमोहल्ला (गुरुद्वारे के सामने), इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। आरएनआई - एमपीएचआईएन/2021/81650
सभी विवादों के लिए न्याय क्षेत्र केवल इंदौर रहेगा। समाचार पत्र में व्यक्तिगत नाम से प्रकाशित खबर एवं आलेख के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।